नई समाजवादी क्रान्ति का उद्घोषक

बिगुल

मासिक समाचार पत्र • वर्ष 3 अंक 1
फरवरी 2001 • तीन रुपये • बारह पृष्ठ

भूकम्प को महज प्रकृति की विनाशलीला घोषित कर खून सने हाथों को साफ नहीं किया जा सकता

26 जनवरी की सुबह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आया भीषण भूकम्प जमीन के भीतर लगातार जारी रहने वाली हलचलों का नतीजा था। यह ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसे रोकना फिलहाल इंसान के वश में नहीं। लेकिन इस भूकम्प से महाविनाश का जो मंजर रचा गया उसे रोकना इंसान के वश में है। इसे प्रकृति की विनाशलीला को नाम देकर उस हत्यारी व्यवस्था के पापों को नहीं धोया जा सकता जो हर पल पकृति और इंसान के लिए विनाश की लीला रचती रहती है।

गुजरात में मची तबाही उस पूंजीवादी व्यवस्था की विनाशलीला है जो इंसान से ज्यादा मुनाफे के लिए फिक्रमन्द रहती है। जब किसी समाज व्यवस्था के केन्द्र में इन्सान न होकर मुनाफा रहेगा तो उस तरह की लापरवाहियां पैदा होंगी जिनके कारण बीस हजार से अधिक लोगों की जानें चली गयीं। जब इस देश की व्यवस्था के कर्ता-धर्ता अपना सारा बुद्धि-विवेक, अपनी सारी ताकत, सारी हरकत इसलिए करते हों कि मुनाफा बढ़ाने के लिए आम मेहनतकश आदमी के खून का एक-एक कतरा कैसे निचौड़ा जाये तो फिर उन्हें इस बात की परवाह भला कैसे हो सकती है कि किसी प्राकृतिक आपदा से निबटने के लिए कौन-कौन सी तैयारियां की जायें, जिससे विनाश को रोका जाये या अधिक से अधिक कम कैसे किया जाये। ऐसा नहीं हो सकता कि रोज-रोज तो कोई व्यवस्था इंसान का खून निचोड़े और बाढ़, सूखा, तूफान और भूकम्प जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के समय संवेदनशील हो जाये।

एक ऐसी समाज व्यवस्था जिसमें सब कुछ के केन्द्र में इंसान हो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले विनाश को रोक सकती है।

सम्पादक

दुनिया में इसके कई उदाहरण हैं जब भूकम्प आने की पहले से चेतावनी लोगों को दी गयी जिससे या तो एक भी मौतें नहीं हुईं या नाममात्र की हुईं। खासकर, चीन, रूस जैसे उन देशों में जहां समाजवादी व्यवस्था कायम थी। चीन के कई इलाके भूकम्प के लिए संवेदनशील हैं। वहां 1949 की क्रान्ति के बाद जब मजदूरों की हुकूमत कायम हुई तो उसने भूकम्प और बाद जैसी आपदाओं का मुकाबला करने के लिए पूरी रणनीति और योजना बनायी। ह्वांगहो नदी, जो हर साल बाढ़ से तबाही मचाती थी, के पानी का सही इस्तेमाल कर न केवल बाढ़ को रोका गया, बल्कि कई नये क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई की व्यवस्था की गयी और बिजली पैदा की गयी। इसी तरह भूकम्प वाले इलाकों की पहचान कर तबाही से बचने के ठोस इंतजाम किये गये। पहले से चेतावनी देने के लिए भूकम्पमापी यंत्र जगह-जगह बनाये गये। झटके बर्दाश्त करने वाले मकान बनाये गये और राहत बचाव की मशीनरी हमेशा चौकस रहती थी।

यहां तक कि बड़े पूंजीवादी देशों ने भी भूकम्प से विनाश के पुराने अनुभवों से सीखते हुए ऐसी व्यवस्था कर ली है जिससे कम से कम नुकसान उठाना पड़े। जाहिर है, यह इन देशों के पूंजीवाद की संवेदनशीलता के कारण नहीं बल्कि सरकारों की उन मजबूरियों के कारण मुमकिन हुआ है, जिसके कारण सत्ता तंत्र जनता की जिन्दगियों के साथ उतना खुला खिलवाड़ नहीं कर सकता जितना तीसरी दुनिया के जालिम पूंजीवादी देशों में होता है। इन देशों के अपने खास इतिहास से पैदा हुए कारणों से जनता की जनतांत्रिक एंव नागरिक अधिकारों की चेतना पिछड़ी है। इसकी वजह से एक संवेदनहीन, भ्रष्ट विलासी, लापरवाह सत्ता तंत्र विकसित हुआ है जो इस हद तक बेखौफ और बेहया है कि मौत की घाटियों में भी रास रचा सकता है। भारत, ईरान, अफगानिस्तान, कोलम्बिया, अल सल्वाडोर जैसे देशों में भूकम्प और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली विनाश लीला का कारण यही है।

हमारे देश का सत्ता तंत्र और समूचा पूंजीवादी कुलीन तंत्र कितना संवेदनहीन, बेशर्म और बेखौफ हो चुका है इसके एक नहीं कई उदाहरण इस भूकम्प के दौरान भी देखने को मिले। भूकम्प को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और दिल्ली में बनावटी मायूस-दुखी चेहरा दूरदर्शनी पर्दे पर दिखाने के चार दिन बाद ही इस देश का ''संवेदनशील-कवि हृदय'' प्रधानमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर मेले-तमाशे और मूर्तियों का उद्घाटन करता है। उसके स्वागत में तोरण द्वार बनाये जाते हैं, अखबारों में अभिनन्दन सन्देश छपवाने की होड़ मचती है। वह मुस्कुराते हुए फोटू खिंचवाता है, सभाओं में बोलते समय गुदगुदाने वाले मजाक करता है। और यह सब करते हुए बेशर्मी से यह घोषणा भी करता है कि वह लखनऊ शोक मनाने आया है। इस ''शोक आयोजन'' में दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो गये।

मौत की घाटी में रास रचाने वाले प्रधानमंत्री जी अकेले नहीं हैं। भमण्डलीकरण की मलाई चाट रहा समूचा पूंजीवादी कुलीन तबका उनके साथ शामिल है। सभी चुनावी दलों के नेता, पूंजीपतियों-अफसरों, कालाबाजारियों, बिचौलियों, दलालों, सिनेमाई भांडों, क्रिकेट सितारों की पूरी

(पेज 10 पर जारी)

ए.एस.पी. का मजदूर आन्दोलन

प्रबन्धतंत्र ने लिखित समझौते को लात मारी

वेतन न मिलने से मजदूर भुखमरी के कगार पर

(बिगुल संवाददाता)

गजरौला (ज्योतिबाफुलेनगर), 7 फरवरी। आनन्द सीलिंग प्रोडक्ट लि. (ए.एस.पी.) के प्रबन्धतंत्र ने पिछले 19 दिसम्बर को मजदूरों के साथ हुए लिखित समझौते को लात मार दी है। इस अन्धेरगर्दी पर श्रम विभाग ने साजिशाना चुप्पी साध ली है और जिला प्रशासन के अफसरों ने आंख मूंद ली है, जबकि समझौता इनकी मध्यस्थता और मौजूदगी में हुआ था।

अपने जायज हक के लिए सात माह से भी अधिक समय तक चले जुझारू आन्दोलन के दबाव में प्रबन्धतंत्र मजबूर हुआ था कि वह मजदूरों से लिखित समझौता करे। मजदूरों के आन्दोलन से 'निबटने' में नाकाम श्रम विभाग और जिला प्रशासन के सामने समझौते के लिए मालिकान को राजी करने के अलावा कोई और तरीका नहीं सूझा था क्योंकि दमन के सारे हथकण्डे आजमाये जा चुके थे। समझौता वार्ता में मजदूरों और प्रबन्धतंत्र के प्रतिनिधियों के अलावा उप श्रमायुक्त, उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी (पुलिस) भी शामिल थे। लेकिन मजदूरों का खून चूसने वाले सभी कारखाना मालिक हरी घास के सांप होते हैं जो खतरा भांपकर दुबक जाते हैं, लेकिन

(पेज 12 पर जारी)

भीतर के पन्नों पर

एनरॉन का तजुर्बा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूटपाट का आइना है 3
पार्टी की बुनियादी समझदारी 4
चीनी क्रान्ति की सचित्र कथा (ग्यारह) 6
काशीपुर में आदिवासी जनता पर पुलिस फायरिंग 11
मारुति का आन्दोलन समाप्त : मजदूर अकेले-अकेले लड़कर नहीं जीत सकते 12

बागडिगी : एक और सामूहिक हत्याकांड

पिछली दो फरवरी को धनबाद की बागडिगी खदान में पानी भर जाने से 37 मजदूर घुट-घुटकर धीमी मौत मर गये। इसके तीन ही दिन बाद चैतूडीह की खान में भी ठीक ऐसे ही चार मजदूर मारे गये।

राष्ट्रीय अखबारों-पत्रिकाओं में छपी रिपोर्टों के अनुसार तमाम विशेषज्ञ भी इसे महज दुर्घटना नहीं मानते। इस भीषण त्रासदी को वे सुरक्षा इंतजामों में बरती गई आपराधिक लापरवाहियों की देन मानते हैं। पर क्या महज कुछ व्यक्तियों की लापरवाही है। नहीं, कतई नहीं! यह बर्बर हत्या है! ठण्डी हत्या! हमें उन हत्यारे चेहरों की शिनाख्त करनी होगी।

बागडिगी और चैतूडीह के मजदूरों की हत्या की है पूंजी के खूंखार दानव ने। मुनाफाखोरी की हिंस्र हवस ने। उसी लालच ने जो पिछले दशकों में 1000 से ज्यादा खनिकों को दर्दनाक मौत के हवाले कर चुका है। (1971 में कोयला उद्योग के सरकारीकरण को समाजवाद मानने वाले बहुतेरे ईमानदार लोगों का भी यह मानना था कि शायद अब ''खान दुर्घटनाओं'' में होने वाली मौतों का सिलसिला रुक सके। लेकिन चासनाला खान ''दुर्घटना'' के बाद यह बात समझ में आ गयी कि उत्पादन के साधनों का स्वामी सीधे कोई पूंजीपति हो या उसका स्थान पूंजीपतियों की सरकार ले ले, मुनाफा निचोड़ने की तहजीब में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही हालात में मजदूर मुनाफा बढ़ाने वाली एक निर्जीव मशीन बना रहता है जिसकी जिन्दगी की कीमत पूंजीपति या उसकी सरकार के लिए मुनाफे से बढ़कर नहीं होती।

इसी वजह से अरसे से यह मालूम होने के बावजूद कि खान में काम कर रहे मजदूरों के सिर पर मौत का काला साया मंडरा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम नहीं किये गये। इस हत्याकांड के एक हफ्ता पहले ही भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) और खान सुरक्षा महानिदेशालय ने इसी खदान में ''सुरक्षा सप्ताह'' आयोजित किया था जिसमें मजदूरों ने बताया था कि पास की बंद हो चुकी जयरामपुर खदान से पानी का रिसाव हो रहा है।

हादसे के दिन भी खनिकों ने सुरक्षा उपाय किये बिना नीचे जाने से इंकार कर दिया था। उनका डर बेबुनियाद है, यह साबित करने के लिए दो अफसर भी खनिकों के साथ नीचे गये और वे भी मौत के शिकंजे में आ गये। इन्हीं में से एक अफसर पी.आर.सिंह ने कोल इंडिया के अध्यक्ष को 15 दिन पहले लिखे पत्र में कहा था कि एक तरफ उन पर कम्पनी द्वारा दिये गये प्रतिमाह उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने का दबाव है और दूसरी ओर कभी भी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। पत्र में खदान की वास्तविक स्थिति की जानकारी देते हुए कहा गया था कि संसाधनों की कमी की वजह से

(पेज 11 पर जारी)

पिछले 45 साल में धनबाद की कोयला खदानों में हुए 10 बड़े हत्याकांड

वर्ष	खदान	मृतक
1955	अमलाबाद	52
1958	सेंदूल बौरा	23
1965	धोरी	268
1973	चूनूडीह	48
1975	केसरगढ़	48
1975	चासनाला	388
1976	सुदामाडीह	43
1995	गजलीटांड	75
1998	बेड़मो	11
2001	बागडिगी	37

''अगर सरकार मजदूरों की जिन्दगी को इतना सस्ता नहीं समझती तो हर हादसा होने से बचाया जा सकता था।''—धनबाद के पूर्व सांसद और खदान कामगार यूनियन के नेता ए.के. राय

आपस की बात

मजदूरों के अरमान चिमनियों से धुआं बनकर निकलते हैं

लुधियाना से दिल्ली को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है—हीरो साइकिल्स लिमिटेड का दैत्याकार कारखाना। हीरो का नाम पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। कम्पनी का दावा है कि उसकी बनाई हुई साइकिलें पूरी दुनिया में अन्य सभी साइकिलों से अधिक बिकती हैं। हीरो कम्पनी अब तो विदेशी पूंजीपतियों से गंठजोड़ करके अन्य दुपहिया वाहनों का उत्पादन भी कर रही है।

हीरो कम्पनी द्वारा खड़े किये गये इस विशाल औद्योगिक साम्राज्य के पीछे हजारों मजदूरों की मेहनत है, जो दिन-रात हीरो के कारखानों में खटते हैं। कारखानों में जिनकी हड्डियां गलती-खपती हैं, जिनका खून पसीना बनकर गिरता है, जिनके अरमान कारखानों की चिमनियों से धुआं बनकर निकलते हैं।

लुधियाना स्थित हीरो के कारखाने की ही बात करें तो इन दिनों मालिकों ने मजदूरों पर अपना आतंक राज कायम कर रखा है। इस कारखाने में तीन हजार से भी अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। अभी तक कारखाने में आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में काम चल रहा था। लेकिन अब मालिक 12-12 घंटे की दो शिफ्टों में ही मजदूरों से काम लेना चाहते हैं। इसलिए पूरी एक शिफ्ट के मजदूर फालतू हो गये हैं जिनकी एक-एक करके छंटनी की जा रही है और निकाले जा रहे मजदूरों के हिस्से का काम बाकी मजदूरों से कराया जा रहा है।

मजदूरों को काम से हटाने के लिए मालिक तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे जिस काम में मजदूर माहिर हैं, उस काम से हटा देना, डिपार्टमेण्ट बदल देना। कारखाने में मालिकों ने साइकिल के अलग-अलग पुरजे बनाने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेण्ट बना रखे हैं। मजदूरों की छंटनी की प्रक्रिया भी सारे कारखाने में एक साथ नहीं, बल्कि एक-एक डिपार्टमेण्ट में शुरू की है, ताकि सभी मजदूर एकजुट होकर इसका प्रतिरोध न कर सकें। अक्सर मालिक किसी भी कुशल मजदूर का डिपार्टमेण्ट बदलकर उसको लोडिंग डिपार्टमेण्ट में भेज देते हैं, जहां पर काम बहुत ही कठिन है और जिस मजदूर ने कभी यह काम किया ही न हो उसके लिए तो और भी कठिन है। लोडिंग डिपार्टमेण्ट में मजदूरों से जबरन 16 घंटे काम भी लिया जाता है। दूसरे डिपार्टमेण्ट से इस डिपार्टमेण्ट में भेजे गये बहुत से मजदूर काम छोड़ गये हैं।

धीरे-धीरे मालिक कारखाने में ठेकेदारी प्रणाली लागू कर रहे हैं। जैसे, एक्सपोर्ट पार्ट्स बनाने का सारा काम ही ठेके पर दे दिया गया है। यहां पर मजदूरों के रोजगार की कोई गारण्टी नहीं है और ठेकेदार मनचाही दिहाड़ी देकर मजदूरों से काम लेते हैं। बाकी सारे कारखाने में 'पीस रेट सिस्टम' चल रहा है। मजदूरों को एक निश्चित समय में एक निश्चित उत्पादन करना होता है। अक्सर मालिक मजदूरों को उनकी सामर्थ्य से अधिक काम दे देते हैं। तयशुदा घंटों में यदि पूरा उत्पादन न हो सके तो मजदूरों को और अधिक घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर मजदूर और अधिक काम न कर सके तो उसकी तनख्वाह में से पैसे काट लिये जाते हैं।

यहां पर तनख्वाहें भी बहुत कम हैं। नये भरती होने वाले मजदूर को तो महज 1500 रुपये ही मिलते हैं। पांच-छह साल कारखाने में काम करने के बाद 2500 या 2600 रुपये ही पाते हैं। पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस साल से कारखाने में काम कर रहे मजदूरों की तनख्वाह 3000 रुपये या इससे कुछ अधिक है। लेकिन ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत ही कम है।

इस कारखाने में कभी भी मजदूरों की यूनियन नहीं बन पाई। जब भी ऐसी कोई कोशिश हुई तो मालिकों ने यूनियन बनाने की कोशिश करने वाले मजदूरों को कारखाने से बाहर कर दिया।

— महेश कुमार सिन्हा
लुधियाना

पार्टी की बुनियादी समझदारी

(पेज 5 से आगे)

डालने के लिए अनथक उद्यम करना चाहिए तथा कम्युनिज्म के लिए एक दृढ़प्रतिज्ञ योद्धा के रूप में अपने को प्रशिक्षित करना चाहिए।

कुछ जरूरी टिप्पणियां :

1. तीन महान क्रान्तिकारी आन्दोलनों से तात्पर्य है : "वर्ग-संघर्ष, उत्पादन के लिए संघर्ष और वैज्ञानिक प्रयोग।" यह नारा माओ त्से-तुङ ने 1963 में दिया था।

2. "तीन करने योग्य और तीन न करने योग्य" चीजों का पार्टी-उसूल निम्नलिखित है : "मार्क्सवाद पर अमल करो, और संशोधनवाद पर मत करो; एकताबद्ध हो जाओ, और फूट मत करो; निश्छल और निष्कपट बनो, और साजिश और सांठगांठ मत करो।"

(अगले अंक में जारी)

काशीपुर (उड़ीसा) में अल्युमिनियम कारखाने के लिए उजाड़ी जा रही आदिवासी जनता पर पुलिस फायरिंग

(पेज 11 से आगे)

पिछले 20 वर्षों से काशीपुर में अपना धंधा चला रहा था। आंदोलन की शुरुआत में हस्ताक्षर अभियान आदि चलाने तथा परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए स्थानीय लोग 'अग्रगामी' से मदद लेते थे। हालांकि इसके पहले ही लोगों ने स्वत:स्फूर्त ढंग से कारखाने के लिए सर्वेक्षण कार्य का विरोध किया था। सर्वे टीमों को गांवों में घुसने से रोक दिया था। और सर्वे के उपकरण छीन लिये थे। ऐसे उग्र तेवर एनजीओ को भा नहीं रहे थे। वह तो आन्दोलन को सुरक्षित सीमाओं और कानून के दायरे के भीतर ही चलाना चाहता था। कुछ सुधारवादी कामों के जरिये लोगों के बीच में अपनी एक छवि बना चुकने के बाद एनजीओ के लिए इतनी बड़ी समस्या से सीधे पीछे हट जाना सम्भव नहीं था। इसलिए उसने पूरे आन्दोलन को नियंत्रित करने और उसकी धार कुंद करने की कोशिश की ताकि उसके अपने अस्तित्व पर खतरा न आये और उसका कारोबार चलता रहे।

हालांकि उसका प्रयास सफल नहीं हुआ लेकिन सरकार और कम्पनी का गंठजोड़ एनजीओ को निशाना बनाकर मीडिया और जनता का ध्यान आन्दोलन के जुझारू तेवर और उसकी अपनी ताकत से भटकाने में कामयाब रहा है।

● रंजना पाढी
(वर्कर्स सॉलिडेरिटी) की रिपोर्ट पर आधारित

नकली कम्युनिस्टों को परखने की कसौटी है "बिगुल"

1947 की आजादी से आज तक हमारे देश में चुनावी कम्युनिस्टों की कई राज्यों में सरकारें बनी, यहां तक कि केन्द्र में भी संयुक्त मोर्चा सरकार के रूप में संसदीय वामपंथियों ने सत्ता सुख भोगा। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुल्क में वामपंथी आन्दोलन आज चिन्ताजनक स्थिति में मौजूद है। प्राय: माना जाता है कि लाल झण्डे वाली हर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है और पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थक तक "कामरेड" हैं। ये चुनावी पार्टियां अपनी सदस्यता को परमात्मा के प्रसाद की तरह गली-कूचों में बांटती नजर आती हैं। इनके कार्यकर्ता सट्टेबाजी दलाली व चोरी जैसे कार्यों में लिप्त पाये जाते हैं। चुनावी वामपंथी 'कामरेड' शब्द को ऐसे बांटते हैं जैसे कि बीमारों में दवाई बांटी जाती है। कहीं-कहीं इनके कार्यकर्ता छिटपुट रूप से ईमानदार व सुधारवादी किस्म से कुछ करते दिखाई देते हैं। लेकिन पार्टी लाइन गलत होने के कारण भटकाव का शिकार हो जाते हैं। जिस मार्क्सवाद के नाम हमारे देश के चुनावी और नकली वामपंथियों ने इतना तामझाम इकट्ठा किया है, उसी मार्क्सवादी दर्शन एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ये पार्टियां पूरी तरह निषेध करती हैं। अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मार्क्सवादी शिक्षा से लैस करके ये अपने लिए मौत का खतरा मोल नहीं ले सकती हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो "सर्वहारा की मुक्ति" से चुनावी वामपंथियों का कुछ लेना-देना नहीं है और सर्वहारा क्रान्ति की बात तो इनके एजेण्डे से कोसों दूर है। चुनावी वामपंथी पूंजीवादी संसद को हर हाल में बचाये रखना चाहते हैं और संसद के रास्ते से समाजवाद लाना चाहते हैं। विश्व की तमाम मजदूर क्रान्तियों के इतिहास को चुनावी वामपंथी एक झटके में नकार देते हैं।

यह देखकर बहुत दुख होता है कि मेहनतकशों का लाल परचम आज नकली वामपंथियों के काले कारनामों से कलंकित हो रहा है। क्रान्ति और क्रान्तिकारियों के मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है। ऐसे पस्तहिम्मती के माहौल में पूरे मुल्क के अन्दर 'बिगुल' ही ऐसा अखबार है जो देश के तमाम पूंजीवादी दलों के काले कारनामों का पर्दाफ़ाश करते हुए नकली वामपंथियों को सरेबाजार नंगा कर देता है।

बिगुल हमें ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण करने का मार्ग दर्शाता है और मार्क्सवादी दर्शन की रोशनी में अंधेरे और कंटीले रास्तों पर चलना सिखाता है। बिगुल का पाठक सहज ही नकली वामपंथियों की पहचान कर लेता है। ऐसे समय में जब एक तरफ पूंजीपतियों की दलाल पार्टियां देश के मेहनतकश अवाम को तरह-तरह से गुमराह कर क्रान्तिकारी आन्दोलन को नेतस्तनाबूद करने पर तुली हैं, वहीं नकली संसदीय वामपंथियों द्वारा आम अवाम को लाल झण्डे के नामपर गुमराह किया जा रहा है। ऐसे समय में बिगुल ही सच्चा पथ प्रदर्शक, राजनैतिक शिक्षक की कमी को पूरा करने का कार्य कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेहनतकश जनता के सच्चे पथ प्रदर्शक 'बिगुल' का साथ देने में हमारे देश की मेहनतकश जनता नहीं हिचकेगी।

— पुखराज निराला
गजरौला, ज्योतिबाफुलेनगर (उ.प्र)

जनता भरेगी नये टैक्स

(पेज 3 से आगे)

कर वसूलने के व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं। ग्राम पंचायतें अब भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति एक रुपये पर पच्चीस से पचास पैसे तक पंचायत कर के रूप में ले सकती हैं। अपनी सीमा के अन्दर चलने वाले मनोरंजन के साधनों (सिनेमा, सर्कस, नौटंकी आदि) से पांच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मनोरंजन कर, पालतू जानवरों पर प्रति पशु छह रुपये के हिसाब से वार्षिक कर, ईंधन से चलने वाले वाहनों पर छह रुपये बतौर कर, पंचायत सीमा के अन्दर लगने वाले मेलों, बाजारों में सामान बेचने वालों से भी कर वसूल कर सकती हैं। ग्राम पंचायतों के अधीन मेलों में पशुओं की बिक्री की रजिस्ट्री पर फीस लगेगी व बूचड़खानों से फीस ली जायेगी। यही नहीं अब पंचायती राज की जनता पंचायतों को सड़कों की सफाई, स्ट्रीट लाइट आदि के नाम पर भी अतिरिक्त टैक्स भरेगी।

अब टैक्स के दायरे से सिर्फ हवा और धूप बची है। देखना है पंचायती राज की नजर इधर कब जाती है।

बिगुल का स्वरूप, उद्देश्य और ज़िम्मेदारियां

1. 'बिगुल' व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मजदूरों के बीच क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओं से, अपने देश के वर्ग संघर्षों और मजदूर आंदोलन के इतिहास और सबक से मजदूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूंजीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।

2. 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा।

3. 'बिगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मजदूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और व्यवहार में सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो।

4. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के बीच लगातार राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्थिक संघर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भुजाछोर "कम्युनिस्टों" और पूंजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी देडयूनियनबाजों से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सुधारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की कतारों से क्रान्तिकारी भरती के काम में सहयोगी बनेगा।

5. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

बिगुल यहां से प्राप्त करें

● शहीद पुस्तकालय, द्वारा डा. दूधनाथ, जनगण होम्यो सेवा सदन, **मर्यादपुर**, मऊ ● मौर्या बुक स्टाल, सआदतपुरा (निकट रोडवेज) मऊनाथभंजन, मऊ ● जनचेतना, जाफरा बाजार, **गोरखपुर** ● विजय इन्फार्मेशन सेन्टर, कचहरी बस स्टेशन, **गोरखपुर** ● विश्वनाथ मिश्र, चेतना कार्यालय, **बड़हलगंज**, गोरखपुर ● ओमप्रकाश, 69, बाबा का पुरवा (पुराना), पेपर मिल रोड, निशातगंज, **लखनऊ** ● जनचेतना स्टाल, निकट काफी हाउस, हजरतगंज, **लखनऊ**, (शाम 5 से 8.30) ● राहुल फाउण्डेशन, 69, बाबा का पुरवा (पुराना), पेपर मिल रोड, निशातगंज, **लखनऊ** ● विमल कुमार, बुक स्टाल, निकट नीलगिरि काम्प्लेक्स, ए ब्लाक, इंदिरानगर, **लखनऊ** ● विजय कुमार, 55/3 ई.डब्लू.एस., आवास-विकास कालोनी, **रुद्रपुर**, ऊधमसिंह -नगर ● रामपाल सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास विकास, **रुद्रपुर**, ऊधमसिंह -नगर ● रवीन्द्र कुमार, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय, **पन्तनगर** ● कृष्णगोविन्द सिंह, बी-18, बिड़ला **छात्रावास, बी.एच.यू., वाराणसी** ● प्रोग्रेसिव बुक सेंटर, विश्वनाथ मंदिर गेट, **बीएचयू परियर, वाराणसी** ● राजीव वर्मा, द्वारा डा. जे.पी. वर्मा, बी.पी.82, पटेलनगर, **मुगलसराय** ● राजेन्द्र प्रसाद, रेनु मेडिकल की गली, मुख्य सड़क, रेणुकूट, सोनभद्र ● सत्यम वर्मा, 81, समाचार अपार्टमेंट, मयूर विहार-एक, **दिल्ली** ● ललित सती, एल.आई.सी. फैज रोड शाखा, **दिल्ली** ● नई किरण पुस्तक भण्डार, एफ-56, हरकेश नगर, ओखला, **दिल्ली** ● डी. के. सचान, कृषि विज्ञान केन्द्र, विकास भवन, कलक्ट्रेट, **गाजियाबाद** ● पंकज कुमार, 256, माडल टाउन, **सोनीपत, हरियाणा** ● सुनील कुमार सिंह, सेक्टर-12 बी, 3159, बोकारो इस्पातनगर, **बोकारो** ● गणपतलाल, ग्राम काजी रसूलपुर, पो. तेघड़ा, **बेगूसराय** ● पीपुल्स बुक हाउस, पटना कालेज के सामने, **पटना** ● समकालीन प्रकाशन (प्रा) लि., पुस्तक बिक्री केन्द्र, आजाद मार्केट, पीरमुहानी, **पटना** ● विमर्श, 22, स्वास्तिक काम्प्लेक्स, रसल चौक, नेपियर टाउन, **जबलपुर** ● नरभिन्दर सिंह, द्वारा डा. सुखदेव हुंदल, ग्रा./पो. **संतनगर**, जिला-सिरसा ● राकेश गोरखा, सरस्वती पुस्तक मंदिर, प्रधान नगर, **सिलीगुड़ी, दार्जीलिंग** ● बुक मार्क, 6, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, **कलकत्ता** ● शर्मा बुक स्टॉल, थाना रोड, चराली, **तिनसुकिया**

नेपाल ● विश्व नेपाली पुस्तक सदन, श्रवनपथ, घुटवल, **रुपनदेही** ● विशाल पुस्तक सदन, बिजुआर बाजार, **प्यूठान**, राप्ती अंचल ● विशाल पुस्तक पसल, अस्पताल लाइन, **घुटवल**

एनरॉन का तजुर्बा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूटपाट का आइना है

एनरॉन के हम्माम में सभी चुनावी पार्टियां नंगी हुईं

कोई इस भ्रम में नहीं होगा कि महाराष्ट्र की जनता पर एनरॉन (डाभोल पॉवर प्रोजेक्ट) के बिजली बिलों की मार से पसीजकर मुख्यमंत्री ने परियोजना केन्द्र सरकार के हवाले करने के वास्ते चिट्ठी लिखी है। विलासराव देशमुख की पहली चिन्ता यह है कि यदि एनरॉन का बिल चुकाने से सरकारी खजाना खाली हो जायेगा तो सरकार के मंत्रियों-अफसरों के सैर-सपाटों, पार्टियों-दावतों और मौजमस्ती के लिए पैसा कहां से आयेगा। दूसरी चिन्ता वोट की है। कहीं नाराज जनता अगले चुनाव में सत्ता के गलियारों से सड़क पर लाकर न पटक दे। इसलिए, जब एनरॉन ने सरकार के साथ हुए करार के तहत एक के बाद एक बिल भेजना शुरू कर दिया तो एक दो बिलों के भुगतान के बाद ही सरकार ने हाथ खड़े कर दिये और एनरॉन की "सफेद हाथी" से पूरे देश की जनता को रौंदवाने की सिफारिश कर दी।

अगर केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मान लेती है तो इसका असर क्या होगा इसका अनुमान महाराष्ट्र के अनुभव से ही लगाया जा सकता है। जून 1999 से बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की तरफ से 2500 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। डॉलर और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों से जुड़े होने की वजह से एनरॉन की बिजली लगातार महंगी होती गयी। पिछले साल मई में चार रुपये 90 पैसे की दर से बिजली लेनी पड़ी; जून में चार रुपये 94 पैसे, सितम्बर में छह रुपये 81 पैसे और अक्टूबर में सात रुपये 13 पैसे की दर से एनरॉन ने बिल भेजा। समझौते के तहत अगर महाराष्ट्र बिजली बोर्ड एनरॉन की बिजली न खरीदे तो भी उसे कम से कम एक सौ करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। अगर डाभोल पॉवर प्रोजेक्ट की पूरी उत्पादन क्षमता (695 मेगावाट) की बिजली बोर्ड खरीदे तो हर महीने करीब 270 करोड़ रुपये का बिल अदा करना पड़ेगा।

ये आंकड़े एनरॉन के पहले चरण के हैं। अगर दूसरे चरण को मिलाकर 2000 मेगावाट बिजली ली गयी तो सिर्फ पहले बरस में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये एनरॉन के हवाले करने पड़ेंगे। यानी हर महीने 650 करोड़ रुपये। मौजूदा आर्थिक स्थिति में महाराष्ट्र बिजली बोर्ड सिर्फ 150 करोड़ रुपये हर माह भी देने की स्थिति में नहीं है। एनरॉन से समझौता 20 सालों के लिए किया गया है, जिस दौरान कुल बिल होगा चार लाख करोड़ रुपये। देश के किसी भी राज्य का बिजली बोर्ड तो क्या राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम (एन.टी.पी.सी.) भी इस हालत में नहीं है कि वह इतनी बड़ी रकम अदा कर सके।

परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा लेने का मतलब है एन.टी.पी.सी. बिजली खरीदे। आज की तारीख में एन.टी.पी.सी. 17 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर हर साल लगभग तीन हजार करोड़ रुपये कमा रहा है। इसकी बिजली उत्पादन की दर फिलहाल एक रुपये बीस पैसे प्रति यूनिट है। एनरान की बिजली खरीदने के लिए निगम को हर साल लगभग आठ हजार करोड़ रुपये देने पड़ेंगे जबकि कमाई सिर्फ तीन हजार करोड़ रुपये हैं। एनरान को भुगतान करने के लिए निगम को राज्य बिजली बोर्डों को बिजली बेचने ही पड़ेंगी। राज्य बिजली बोर्ड जब खरीदेंगे तो निगम का बिल चुकाने के लिए जनता से ही वसूलेंगे। एक अनुमान के अनुसार एनरॉन की बिजली दर बढ़ने की जो रफ्तार है, उसे देखते हुए 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से जनता से वसूला जायेगा तभी एनरॉन का बिल चुकाया जा सकता है।

एनरॉन की लूटपाट के लिए पूरे देश में रास्ता खोलने की तैयारी

एनरॉन का यह तजुर्बा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा दुनिया भर में की जा रही लूटपाट का एक आइना है। सरकारों से सौदा पटाने में यह अमेरिकी कम्पनी अपने देश की तमाम कम्पनियों में सबसे ऊपर जगह रखने वालों में शामिल हैं। अपने प्रोजेक्ट की फाइल पास कराने के लिए यह तीसरी दुनिया के देशों की सरकारों और तमाम सत्ताधर्मी राजनीतिक दलों के वजनदार नेताओं को घूस की मोटी रकमें खिलाने में उस्ताद है। बात जब इससे नहीं बनती तो यह अपनी सरकार पर अपने रुतबे का इस्तेमाल कर तीसरी दुनिया की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए कहती है। एनरॉन के मालिकान अपने देश की सरकार के कामकाज पर जबर्दस्त दबाव रखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जार्ज बुश सीनियर के साथ एनरॉन की गहरी यारी थी। यह यारी जार्ज बुश जूनियर के साथ भी खूब छनेगी और उसका लूटपाट का धंधा खूब फलेगा-फूलेगा।

एनरॉन के भारत में हुए सौदे की कहानी अब उजागर हो चुकी है कि किस तरह घूस खिलाकर प्रोजेक्ट पास कराया गया ओर बिजली दर के बारे में झूठ-मूठ के वायदे इसने किये थे। 20 जून 1992 को उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार (आज वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख भी इसी पार्टी के हैं) ने तमाम नियमों कानूनों को ताक पर रखकर कागज पर साइन कर दिया था। आज भी वे अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से तकरार कर खुलेआम एनरॉन के साथ खड़े हैं और मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व कैबिनेट सचिव डा. माधवराव गाडबोले की अगुवाई में बनी जांच समिति में अपने चहेते अफसरों को घुसाया। ये अफसर एनरॉन सौदे को पास कराने वालों में रहे हैं, इसलिए प्रदेश की साझा सरकार में शामिल दूसरी पार्टियों ने अपनी फजीहत से बचने के लिए इन नामों का जबर्दस्त विरोध कर दिया, जिससे रंग में भंग पड़ गयी। लेकिन पवार अड़े हैं कि एनरान सौदा रद्द न किया जाये, उससे बातचीत कर बिजली की दर कम करवायी जाये।

महाराष्ट्र राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे (भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), जो पिछले चुनाव प्रचार के दौरान एनरॉन को समुन्दर में फेंक देने के लिए दहाड़ लगा रहे थे, जब मुख्यमंत्री बने तो एनरॉन को वापस लाने में भी उतनी ही बहादुरी दिखायी। आज एनरॉन को देशनिकाला करने के बजाय समझाने-बुझाने के पक्ष में हैं। यह बात सभी को याद होगी कि भाजपा सरकार के ऐतिहासिक तेरह दिनी कामकाज में ही सरकार गिरने के दिन कैबिनेट की इमर्जेन्सी मीटिंग में एनरॉन को काउण्टर गारण्टी दी गयी थी। प्रमोद महाजन ने इसमें खास भूमिका निभायी थी।

कांग्रेसियों ने भी एनरॉन को देश में लाने के लिए काफी उतावलापन दिखाया था। पूर्व वित्तमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने वित्त सचिव मोंटेक सिंह अहलूवालिया से कहकर एनरॉन को केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की मंजूरी दिलवायी थी। शिवसैनिकों ने एनरॉन के खिलाफ काफी उत्पात मचाया था, लेकिन एनरॉन की प्रतिनिधि रेबेका मार्क उनके सरदार बाल ठाकरे से मिली और ठाकरे ने हरी झंडी दी तब एनरॉन का कामकाज शुरू हुआ।

साफ है कि एनरॉन के हम्माम में पक्ष-विपक्ष के सभी चुनावी दल नंगे हैं। इसीलिए आज ज्यादातर या तो चुप हैं या खुलकर एनरॉन को बचाने में लगे हैं। केन्द्र सरकार भी एनरॉन को देश निकाला दे नहीं सकती, क्योंकि वह भी समझौते से बंधी है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिल भुगतान से इंकार करने के बाद उसने केन्द्र सरकार को बिल भेज दिया। अब केन्द्र सरकार एनरॉन के उद्धार के लिए उसे खुद पालने-पोसने का फैसला करती है तो इसका मतलब होगा पूरे देश की जनता की लूटपाट के लिए एनरॉन का रास्ता साफ करना।

मुकुल श्रीवास्तव

राजनीतिक कारणों से हुए तबादलों के खिलाफ संघर्षरत बिजली कर्मियों पर बर्बर लाठीचार्ज

(बिगुल प्रतिनिधि)

भटिण्डा (पंजाब)। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को "सुधारने" के नाम पर देश भर में अलग-अलग राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों को तोड़ने और उन्हें देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। साथ ही, इस जनविरोधी सरकारी कदम का विरोध कर रहे लोगों पर सरकारी दमन और पुलिसिया कहर भी कमोबेश पूरे देश में बरपा हो रहा है। पंजाब के भटिण्डा जिले में विगत 10 जनवरी को बिजली कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा किया गया लाठी चार्ज और पथराव इसका एक ताजा उदाहरण है। बिजली कर्मचारी अपने नेताओं के नाजायज तबादलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे जो निजीकरण के खिलाफ संघर्ष का ही एक अंग था।

दरअसल, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड का निजीकरण पिछले लम्बे समय से पंजाब के हुक्मरानों के एजेण्डे पर है। इस निजीकरण की राह में सबसे बड़ी रुकावट है—बिजली कर्मियों की लड़ाकू जत्थेबन्दी—'टेक्नीकल सर्विसेज यूनियन' (टी.एस.यू.)। टी.एस.यू. की राज्य समिति पर संशोधनवादी पार्टी सी.पी.एम. से जुड़े हुए लोग काबिज हैं, जिनका नई आर्थिक नीतियों से कोई विरोध नहीं है। निजीकरण के खिलाफ इनकी लड़ाई दिखावा मात्र है। लेकिन इसके बावजूद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टी.एस.यू. में कई सर्किलों में नेतृत्व क्रान्तिकारी ताकतों के हाथ में है। टी.एस.यू. की अधिकांश सदस्यता टी.एस.यू. में काम कर रही क्रान्तिकारी ताकतों के प्रभाव में है। यही वजह है कि पंजाब में टी.एस.यू. एक लड़ाकू संगठन के रूप में स्थापित है।

क्रान्तिकारी ताकतों के प्रभाव वाले सर्किलों में बिजलीकर्मी अपनी मांगों के लिए लड़ने के साथ-साथ स्थानीय जन संघर्षों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसीलिए पंजाब में सत्ता में आने वाली हर पार्टी बिजली कर्मियों की एकता को तोड़ने के प्रयास करती है। पिछले साल भटिंडा जिले के जेठुके गांव में, प्राइवेट बस मालिकों द्वारा यात्रियों से वसूले जा रहे नाजायज बस किराये के खिलाफ, आन्दोलन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई थीं, जिसमें दो बेकसूर खेत मजदूर मारे गये थे। इस हत्याकांड के खिलाफ क्रान्तिकारी जनसंगठनों के नेतृत्व में चले आन्दोलन में भटिंडा सर्किल के बिजली कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे।

जेठुके गांव के आन्दोलन के बाद बिजली कर्मचारी सत्ताधीशों की आंख की किरकिरी बने हुए थे। राज्य के बिजली मंत्री सिकंदर सिंह मलूका तो भटिंडा जिले के ही रहने वाले हैं। जेठुके गांव के आन्दोलन में वह बस मालिकों की पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन आन्दोलन को मिले व्यापक जनसमर्थन के कारण सरकार, बस मालिकों और पुलिस को आम जनता के सामने झुकने को मजबूर होना पड़ा। तभी से बिजली मंत्री महोदय ने बिजली कर्मचारियों को सबक सिखाने की ठान रखी थी। इसीलिए, मौका देखकर मंत्री के इशारे पर बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने भटिंडा सर्किल के सात टी.एस.यू. नेताओं के दूर-दराज के क्षेत्रों में तबादले कर दिये। चूंकि ये तबादले बदला लेने की भावना के तहत राजनीतिक आधार पर किये गये थे, इसलिए बिजली कर्मियों ने इनके खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया। इसतरह पिछले सात महीने से बिजली कर्मचारी इन तबादलों का विरोध कर रहे थे।

अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों बिजली कर्मचारियों ने 10 जनवरी को 'एक्जीक्यूटिव इंजीनियर' का घेराव किया। सुबह से घेराव कर रहे बिजली कर्मचारियों के घेरे से इस अधिकारी को निकालने के लिए पुलिस ने दोपहर बाद जबर्दस्ती करने की कोशिश की। मगर बिजली कर्मियों ने पुलिस को सफल नहीं होने दिया। तभी 'एक्जीक्यूटिव इंजीनियर' के दफ्तर में खड़े सिविल वर्दी वाले कुछ पुलिस वालों ने बिजली कर्मियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिये। इसके साथ ही पुलिस वाले बिजली कर्मियों पर लाठी भांजने लगे। पुलिस के इस हमले के जवाब में बिजली कर्मियों ने भी पथराव किया। बिजली कर्मियों के इस मुंहतोड़ जवाब से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। बाद में जब बिजली कर्मियों ने अपना कार्यक्रम समाप्त कर दिया और अधिकांश बिजलीकर्मी घेराव स्थल से चले गये, तो पुलिस मौका देखकर पीछे छूट गये कुछ बिजली कर्मियों पर टूट पड़ी। जो भी उनके हाथ आया, उसी को बुरी तरह से पीटा गया। कई बिजली कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 25 कर्मचारियों को धारा 307 जैसी खतरनाक धाराएं लगाकर फर्जी केस में फंसा दिया गया।

टी.एस.यू. पर शासकों का न तो यह पहला हमला है और न आखिरी, भटिंडा तथा अन्य सर्किलों के बिजली कर्मचारी शासकों के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज जहां भी मजदूर कर्मचारी संगठित हैं, वहां सरकार के लिए निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों को लागू करवाना मुश्किल पड़ रहा है, शासकों को जनविरोधी नई आर्थिक नीतियों को अमल में लाने में मजदूरों-कर्मचारियों के तीखे प्रतिरोध का सामना करनाा पड़ रहा है। यह बात पंजाब के लिए भी उतनी ही सही है, जितनी अन्य जगहों के लिए।

पंचायतों से उद्योग मुक्त होंगे और जनता भरेगी नये टैक्स

(बिगुल संवाददाता)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूंजीपतियों को कुछ और रियायतें देते हुए आम जनता पर कुछ और नये टैक्स थोप दिये हैं। सरकार जहां औद्योगिक नगरों के दायरे में आने वाली पंचायतों को समाप्त करने जा रही है वहीं पंचायतों को ग्रामीण जनता से टैक्स वसूलने के अधिकार दे रही है।

प्रदेश सरकार एक अध्यादेश लाकर 1976 में बने उत्तरप्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इस नयी व्यवस्था के तहत पंचायत क्षेत्र में शामिल औद्योगिक क्षेत्र उसके दायरे से मुक्त हो जायेंगे। एक अन्य अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश सरकार यह भी व्यवस्था करने जा रही है कि आप्टिकल फाइबर बिछाने वाली निजी संस्थाओं को किसी भी सरकारी महकमे या पंचायतों से अनुमति लिये बगैर (पहले अनुमति के साथ ही शुल्क की भी अदायगी करनी पड़ती थी) सड़कों की खुदाई करके आप्टिकल फाइबर बिछाने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा।

दूसरी तरफ, सरकार ने जनता पर कुछ नये टैक्स लगाने के अधिकार भी पंचायतों को दे दिये हैं। पंचायती राज मंत्री की एक घोषणा के अनुसार ग्राम पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के लिए

(पेज 2 पर जारी)

विशेष सामग्री

पार्टी की बुनियादी समझदारी

(पहली किस्त)

एक क्रान्तिकारी पार्टी के बिना मजूदर वर्ग क्रान्ति को कतई अंजाम नहीं दे सकता। लेनिन ने इस बात को बार-बार जोर देकर कहा था। स्तालिन और माओ ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया और बीसवीं सदी की सभी सफल सर्वहारा क्रान्तियों ने भी इसे सत्यापित किया।

लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी के सांगठनिक उसूलों का निर्धारण किया और इसी फौलादी सांचे में बोल्शेविक पार्टी को ढाला। चीन की पार्टी भी बोल्शेविक पार्टी की ही उत्तराधिकारी थी। **सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति** के दौरान, समाजवादी समाज में वर्ग-संघर्ष का संचालन करते हुए माओ के नेतृत्व में चीन की पार्टी ने अन्य युगान्तरकारी सैद्धान्तिक उपलब्धियों के साथ-साथ लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्तों को भी और आगे विकसित किया।

सोवियत संघ और चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के लिए बुर्जुआ तत्वों ने सबसे पहले यही जरूरी समझा कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी का चरित्र बदल दिया जाये। हमारे देश में भी संसदीय रास्ते की अनुगामी नामधारी कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद हैं। भारतीय मजदूर क्रान्ति को सफल बनाने के लिए भारत में भी सर्वहारा वर्ग की एक सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने का काम सर्वोपरि है।

इसके लिए बेहद जरूरी है कि मजदूर वर्ग यह जाने कि असली और नकली कम्युनिस्ट पार्टी में क्या फर्क होता है और एक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी कैसे खड़ी की जानी चाहिए।

इसी उद्देश्य से, 'बिगुल' के इस अंक से हम एक बेहद जरूरी किताब **'पार्टी की बुनियादी समझदारी'** के अध्यायों का किश्तों में प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। यह किताब सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान पार्टी-कतारों और युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए तैयार की गई श्रृंखला की एक कड़ी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस (1973) में पार्टी के गतिशील क्रान्तिकारी चरित्र को बनाये रखने के प्रश्न पर अहम सैद्धान्तिक चर्चा हुई थी, पार्टी का नया संविधान पारित किया गया था और संविधान पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसी नई रोशनी में यह पुस्तक एक सम्पादकमण्डल द्वारा तैयार की गई थी। मार्च, 1974 में **पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, शंघाई** से इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की 4.74.000 प्रतियां छपीं। यह पुस्तक पहले चीनी भाषा से फ्रांसीसी भाषा में अनूदित हुई और 1976 में प्रकाशित हुई। फिर **नार्मन बेथ्यून इंस्टीच्यूट, टोरण्टो (कनाडा)** ने इसका फ्रांसीसी से अंग्रेजी में अनुवाद कराया और 1976 में ही इसे प्रकाशित भी कर दिया। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पुस्तक के इसी अंग्रेजी संस्करण से किया गया है। — सम्पादक

माओ त्से-तुङ के उद्धरण

''हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने में नेतृत्व देने वाली शक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है।''

''हमारे विचारों को मार्गदर्शन करने वाला सैद्धान्तिक आधार मार्क्सवाद-लेनिनवाद है।''

''क्रान्ति को विजय की मंजिल तक पहुंचाने के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी को खुद अपनी राजनीतिक लाइन के सही होने पर और अपने संगठन की मजबूती पर निर्भर होना चाहिए।''

''मार्क्सवाद पर अमल करो, और संशोधनवाद पर मत करो; एकताबद्ध हो जाओ, और फूट मत करो, निश्छल और निष्कपट बनो, साजिश और सांठगांठ मत करो।''

अध्याय 1

पार्टी का चरित्र

दसवीं कांग्रेस के दौरान स्वीकृत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान यह निर्दिष्ट करता है कि ''चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक पार्टी, सर्वहारा वर्ग का हरावल है।'' यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पार्टी की प्रकृति के बारे में सही समझदारी कायम करें ताकि इसका निर्माण करने में और इसके केन्द्रीकृत नेतृत्व को सुदृढ़ बनाने में सहायक बना जा सके, सर्वहारा के हरावल के तौर पर इसकी नेतृत्वकारी भूमिका को पूर्णत: क्रियाशील बनाया जा सके, और हमारे देश में समाजवादी लक्ष्य के लिए लगातार बड़ी से बड़ी जीतें सुनिश्चित की जा सकें।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक पार्टी है

मार्क्सवाद यह शिक्षा देता है कि एक राजनीतिक पार्टी वर्ग-संघर्ष की उपज होती है और साथ ही, उसका उपकरण होती है। वर्ग समाज में, यदि एक वर्ग-विशेष विरोधी वर्गों के विरुद्ध संघर्ष के लिए अपनी शक्तियों को गोलबन्द और संगठित करना चाहता है, और उनसे सत्ता छीन लेना चाहता है, और उस सत्ता का सुदृढ़ीकरण करना चाहता है, और पूरे समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना तथा कायम रखना चाहता है, तो उसे अपने लिए एक संगठन का और एक नेतृत्व का निर्माण करना होगा, जो उसके हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, और जो इसके संकल्प को केन्द्रीभूत रूप में प्रकट करता हो—एक राजनीतिक पार्टी यही करती है। जैसा कि लेनिन ने कहा है, **''...वर्गों का नेतृत्व राजनीतिक पार्टियां करती हैं...।''** राजनीतिक पार्टी वर्ग का केन्द्रक होती है और वर्ग राजनीतिक पार्टी का आधार होता है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अनिवार्य रूप से एक स्पष्टत: परिभाषित वर्ग-चरित्र होता है। दुनिया में कभी भी वर्गों से ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही है, न ही कभी ''समूची जनता की पार्टी'' जैसी किसी ऐसी चीज का कोई अस्तित्व रहा है जो किसी सुनिश्चित वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व न करती हो।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक सर्वहारा राजनीतिक पार्टी है, यह सर्वहारा वर्ग का हरावल दस्ता है, जिसका निर्माण मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्रान्तिकारी सिद्धान्त और कार्यशैली के आधार पर हुआ है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक सर्वहारा पार्टी है क्योंकि यह सर्वहारा वर्ग की अभिलाक्षणिकताओं और गुणों की संकेन्द्रित अभिव्यक्ति है। सर्वहारा मानव जाति के इतिहास का महानतम वर्ग है, यह विचारधारात्मक और राजनीतिक रूप से तथा सामर्थ्य की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली क्रान्तिकारी वर्ग है; यह सर्वाधिक उन्नत आर्थिक रूपों से जुड़ी हुई, नई उत्पादक शक्तियों का प्रतिनिधि है। पुराने समाज में, यह सर्वहारा वर्ग ही था जिसे सबसे क्रूर शोषण और सबसे खूंखार उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। इसके पास कुछ भी नहीं था, उत्पादन के साधनों पर इसका कोई स्वामित्व नहीं था और खुद को जिन्दा रखने के लिए यह पूरी तरह से, अपनी श्रमशक्ति के विक्रय पर निर्भर था। अपनी आर्थिक और राजनीतिक अवस्थिति के चलते, सर्वहारा वर्ग शोषक वर्गों के प्रति सर्वाधिक घृणा का भाव रखता था, इसका परिप्रेक्ष्य सर्वाधिक व्यापक था, और व्यक्ति के मुकाबले समूह के प्रति इसका सरोकार सबसे ज्यादा था। सर्वहारा वर्ग क्रान्ति में सर्वाधिक आमूल परिवर्तनवादी था और अनुशासन एवं संगठन के बारे में इसकी समझ सबसे अधिक पक्की थी। चीनी सर्वहारा वर्ग वस्तुत: तिहरे उत्पीड़न का शिकार था : साम्राज्यवाद का उत्पीड़न, पूंजीवाद का उत्पीड़न और सामन्तवाद का उत्पीड़न—दरअसल दुनिया में बहुत कम ही ऐसी जगहें हैं जहां उत्पीड़न इतने क्रूर और भंयकर किस्म का रहा हो। यही कारण है कि, क्रान्तिकारी संघर्ष में, दूसरे किसी वर्ग की अपेक्षा चीनी सर्वहारा वर्ग अधिक दृढ़ और कृतसंकल्प था। साथ ही, चीनी सर्वहारा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बेदखल किसानों के बीच से आता था और इसलिए उस किसान जन समुदाय के साथ, जो आबादी की भारी बहुसंख्या थे, उसका स्वाभाविक जुड़ाव बनता था। इसतरह, सर्वहारा वर्ग और किसान आबादी को एकताबद्ध करना अपेक्षतया अधिक सुगम हो गया। इन सभी कारणों के चलते, क्रान्तिकारी संघर्ष में, चीनी सर्वहारा वर्ग सर्वाधिक क्रान्तिकारी और सर्वाधिक साहसी सिद्ध हुआ। किसी भी खतरे या कुर्बानी से पीछे हटे बगैर, यह हमेशा क्रान्तिकारी संघर्ष की अगली कतारों में बना रहा और इसतरह, यह चीनी क्रान्ति की अजेय नेतृत्वकारी शक्ति बन गया। और ठीक यही वह सर्वाधिक कृतसंकल्प, सर्वाधिक प्रगतिशील और सर्वाधिक क्रान्तिकारी वर्ग है जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना वर्ग-आधार पाया है। इसतरह, हमारी पार्टी में, न सिर्फ सर्वहारा वर्ग की सभी विशिष्ट अभिलाक्षणिकताएं और गुण मौजूद हैं, बल्कि यह चीनी सर्वहारा वर्ग की इन सभी अभिलाक्षणिकताओं और गुणों की संकेन्द्रित अभिव्यक्ति भी है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी क्यों एक सर्वहारा राजनीतिक पार्टी है, इसका एक अन्य कारण यह है कि यह चीन के क्रान्तिकारी आन्दोलन में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अमल की उपज है। अपने जन्म के दिन से ही चीनी सर्वहारा वर्ग ने अपने शोषकों और उत्पीड़ितों का प्रतिरोध करना कभी बन्द नहीं किया। बेशक, 4 मई आन्दोलन के पहले चीनी मजदूर वर्ग अभी भी स्वत:स्फूर्त संघर्ष की मंजिल में था और एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित नहीं हो पाया था। 1919 में, अक्टूबर क्रान्ति और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रभाव में, साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के विरुद्ध, हमारे देश में 4 मई आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। इस महान क्रान्तिकारी आन्दोलन के दौरान, चीनी सर्वहारा इतिहास के मंच पर एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आया और उसने अपने असीम शक्ति और बढ़ते हुए आकार को प्रदर्शित किया। साथ ही, 4 मई आन्दोलन ने उन कुछ बुद्धिजीवियों को भी प्रेरित किया जो कुछ प्रारम्भिक कम्युनिस्ट विचार रखते थे—इन बुद्धिजीवियों ने, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अध्ययन और प्रचार-प्रसार की महत्ता से और सर्वहारा वर्ग की ऐतिहासिक अवस्थिति से परिचित होने के बाद, व्यापक जनता के बीच मार्क्सवाद के प्रचार का काम शुरू किया, और इसतरह इन्होंने अपने को मजदूरों और किसानों के साथ एकरूप कर देने का रास्ता पकड़ा। 4 मई आन्दोलन ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सार्वभौमिक सच्चाई को चीनी क्रान्ति के ठोस व्यवहार में लागू करने की शुरुआत को चिन्हित किया। इसने—विचारधारात्मक स्तर पर और कार्यकर्ताओं के सन्दर्भ में, दोनों ही धरातलों पर—पार्टी की स्थापना के लिए परिस्थितियां तैयार करने का काम किया। चीनी क्रान्तिकारी आन्दोलन में मार्क्सवाद-लेनिनवाद को लागू करने की शुरुआत के साथ ही, अध्यक्ष माओ के प्रतिनिधित्व में चीनी कम्युनिस्टों ने उत्साहपूर्वक पार्टी खड़ी करने के काम को हाथ में लिया। । जुलाई 1921 को, देश के सभी कम्युनिस्ट ग्रुपों ने शंघाई में आयोजित चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे, जहां पार्टी के जन्म की औपचारिक घोषणा की गई। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया दिखलाती है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण आधुनिक चीन में सर्वहारा क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकास का अपरिहार्य फल था, और यह कि पार्टी चीन के क्रान्तिकारी आन्दोलन में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अमल से पैदा हुई थी।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी क्यों एक सर्वहारा राजनीतिक पार्टी है, इसका एक और भी कारण यह है कि यह सर्वहारा वर्ग के बुनियादी हितों और वर्ग संकल्प का संकेन्द्रित रूप में प्रतिनिधित्व करती है, और कि यह चीन की और पूरी दुनिया की जनता की बहुसंख्यक आबादी के हितों की सेवा करती है। सर्वहारा के महान शिक्षक मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र में लिखा है : **''पहले के तमाम ऐतिहासिक आन्दोलन अल्पमत के आन्दोलन रहे हैं, या अल्पमत के फायदे के लिए रहे हैं। किन्तु सर्वहारा आन्दोलन विशाल बहुमत का, विशाल बहुमत के फायदे के लिए होने वाला चेतन और स्वतंत्र आन्दोलन है।''** अध्यक्ष माओ ने भी कहा है : **''कम्युनिस्ट पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्र और जनता के हित में काम करती है और प्राप्त करने के लिए और दूसरा कोई भी निजी लक्ष्य इसके सामने नहीं होता।''** ये शिक्षाएं सर्वहारा राजनीतिक पार्टी के चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं और पार्टी तथा सर्वहारा व अन्य मेहनतकश जनता के बीच हितों की अभिन्नता को प्रतिबिम्बित करती हैं। पार्टी की स्थापना सामूहिक हित के लिए या निजी स्वार्थ के लिए—यही वह चीज है जो सर्वहारा पार्टी को किसी बुर्जुआ राजनीतिक पार्टी से अलग करती है। सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग और सभी शोषक वर्गों को पूरीतरह उखाड़ फेंकने के लिए, शोषण की सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देने के लए और सर्वहारा वर्ग तथा समूची मानवता की सम्पूर्ण मुक्ति हेतु संघर्ष करने के लिए अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी स्थापित करता है—इसका मतलब है कि यह सामूहिक हित के लिए, क्रान्ति के लिए, जनता के लिए एक पार्टी स्थापित करता है। लेकिन इसके विपरीत, सभी बुर्जुआ या संशोधनवादी पार्टियां शोषक वर्गों के हितों की सुरक्षा में, बुर्जुआ वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग और समूची मेहनतकश जनता के शोषण की क्रूर व्यवस्था की हिफाजत में अपने प्रयासों को निर्देशित करती हैं—ऐसी पार्टियां स्थापित करने का मतलब है अपने आप के लिए ऐसा करना, मुट्ठी भर लोगों के निजी हितों की सेवा के लिए ऐसा करना, शोषक वर्गों की सेवा में लगे होना। अपनी स्थापना के दिन से ही, हमारी पार्टी ने सर्वहारा वर्ग के बुनियादी हितों के लिए, इसके उच्चतम आदर्श : कम्युनिज्म की प्राप्ति के लिए अनथक संघर्ष किया है। जनवादी क्रान्ति के युग में अध्यक्ष माओ ने सशस्त्र संघर्ष के जरिए सत्ता कब्जा करने के रास्ते पर समूची पार्टी और जनता का नेतृत्व किया और इसतरह उन्होंने ''तीन बड़े पहाड़ों'' को उखाड़ फेंका जो चीनी जनता को कुचल रहे थे, तथा नये चीन की स्थापना की। समाजवादी क्रान्ति की अवधि में, एक बार फिर, सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तर्गत क्रान्ति को जारी रखने के अध्यक्ष माओ के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए, हमारी पार्टी ने आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक मोर्चों पर समाजवादी क्रान्ति को जारी रखने में हमारे देश के सर्वहारा वर्ग और जनता का नेतृत्व प्रदान किया। और सबसे ऊपर, यह व्यक्तिगत तौर पर माओ द्वारा शुरू की गई और उन्हीं के नेतृत्व में संचालित, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति ही रही है जिसने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को अभूतपूर्व रूप से मजबूत बनाया और जिसने हमारे देश में समाजवाद के विकास को महान छलांगों के द्वारा तेज गति प्रदान की। अन्तरराष्ट्रीय मोर्चे पर, हमारी पार्टी, सर्वहारा अन्तरराष्ट्रीयतावाद पर दृढ़तापूर्वक कायम रहते हुए, दुनिया के सभी सच्ची मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों एवं संगठनों के साथ एकता बनाती है, और उस आधुनिक संशोधनवाद का कृतसंकल्प विरोध करती है, जिसका प्रतिनिधित्व गद्दार सोवियत संशोधनवादियों का गिरोह करता है। अपने अस्तित्व के पचास वर्षों की पूरी अवधि के दौरान, हमारी पार्टी का इतिहास सर्वहारा वर्ग और मेहनतकश जनता के बुनियादी हितों के लिए, समूची मानवता की मुक्ति के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। यह सभी तथ्य स्पष्टत: दिखलाते हैं कि हमारी पार्टी एक सर्वहारा राजनीतिक पार्टी है।

पार्टी सर्वहारा वर्ग का हरावल* है

हमारी पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्ग के रूप में सर्वहारा से, इसको अलग करती हैं। पार्टी में सर्वहारा वर्ग का सिर्फ एक हिस्सा, उसका सर्वाधिक कृतसंकल्प, सर्वाधिक संघर्षशील हिस्सा ही शामिल होता है—यह सर्वहारा वर्ग का हरावल होता है। अध्यक्ष माओ इसकी स्पष्टतापूर्वक व्याख्या करते हैं **''पार्टी संगठन सर्वहारा वर्ग के अग्रिम तत्वों से संघटित**

*हरावल—आगे चलने वाला दस्ता —स.

(पेज 5 पर जारी)

होना चाहिए; इसे ऊर्जस्वी हरावल संगठन होना चाहिए जो वर्ग शत्रु के विरुद्ध संघर्ष में सर्वहारा वर्ग और क्रान्तिकारी जन-समुदाय का नेतृत्व कर पाने में सक्षम हो।''

हमारी पार्टी सर्वहारा वर्ग का हरावल है, क्योंकि यह सर्वहारा वर्ग के अग्रिम तत्वों से संघटित हुई है। सर्वहारा वर्ग के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते, न ही सभी क्रान्तिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं—इसमें सिर्फ वही शामिल हो सकते हैं जो सर्वहारा वर्ग के भीतर के सर्वाधिक दृढ़संकल्प अग्रिम तत्व हों, और वे लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक मिशन के प्रति असीम समर्पण भाव प्रदर्शित किया हो। बेशक हमारी पार्टी में सिर्फ सर्वहारा मूल के ही सदस्य नहीं हैं, ऐसे भी सदस्य हैं जो दूसरे सामाजिक वर्गों से आते हैं। लेकिन ये क्रान्तिकारी जो सर्वहारा मूल के नहीं हैं, पार्टी में दूसरे वर्गों के प्रतिनिधियों के तौर पर नहीं आते हैं। उन्हें सदस्यता केवल तभी दी जाती है, जब वे सचेतन तौर पर अपने विश्व दृष्टिकोण को बदल देते हैं, सर्वहारा विचारधारा को आत्मसात कर लेते हैं, और मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुङ विचारधारा के अध्ययन के बाद अपनी भूतपूर्व वर्ग-अवस्थिति को त्याग देते हैं, तथा तीन महान क्रान्तिकारी आन्दोलनों में हिस्सा लेने लगते हैं। साथ ही, उन्हें सर्वहारा वर्ग के अग्रिम तत्वों के लिए आवश्यक शर्तों को भी पूरा करना होता है। इस तरह, पार्टी में ऐसे कामरेडों का प्रवेश, पार्टी के सर्वहारा चरित्र को बदलने के बजाय, इसकी कतारों को विस्तारित करता है तथा इसकी संघर्ष-क्षमता को मजबूत बनाता है।

हमारी पार्टी सर्वहारा वर्ग का हरावल इसलिए भी है क्योंकि इसकी सोच का मार्गदर्शन करने वाला सैद्धान्तिक आधार मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुङ विचारधारा है। जैसा कि अध्यक्ष माओ कहते हैं : **''अपनी शुरुआत से ही हमारी पार्टी ने स्वयं को मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्त के आधार पर कायम रखा है...।''** लम्बे क्रान्तिकारी संघर्ष की पूरी अवधि के दौरान, चीनी क्रान्ति के ठोस व्यवहार की सेवा के लिए, अध्यक्ष माओ ने मार्क्सवाद का सही ढंग से इस्तेमाल किया। इस तरह उन्होंने मार्क्सवाद को विरासत में हासिल किया, उसकी हिफाजत की और उसे आगे विकसित किया। क्रान्ति के विकास की प्रत्येक ऐतिहासिक मंजिल पर अध्यक्ष माओ ने हमारी पार्टी के लिए सही राजनीतिक लाइन और सही नीतियों को निर्धारित किया है। प्रत्येक अवसर पर, उन्होंने हमारे भीतरी और बाहरी—दोनों किस्म के दुश्मनों की अवसरवादी लाइनों पर जीत हासिल की है, और जीत-दर-जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ने में क्रान्तिकारी लक्ष्य का नेतृत्व किया है। चूंकि हमारी पार्टी ने खुद को मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुङ विचारधारा पर हमेशा ही कायम रखा है और चूंकि इसने हमेशा अध्यक्ष माओ की सर्वहारा क्रान्तिकारी लाइन का अनुसरण किया है; ठीक इसीलिए यह सर्वहारा वर्ग के हरावल के रूप में अपना चरित्र बनाये रखने में सफल रही है, और समूची चीनी जनता का नेतृत्वकारी केन्द्रक बन गई है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शिक्षाओं के अनुसार, कोई पार्टी वास्तव में एक सर्वहारा राजनीतिक पार्टी है या नहीं, वह सर्वहारा वर्ग का हरावल है या नहीं; यह तय करने के लिए सिर्फ इसके सदस्यों के सामाजिक मूल की पड़ताल ही काफी नहीं है, बल्कि इसके बजाय इसके मार्गदर्शक चिन्तन को, इसके कार्यक्रम को और इसकी लाइन को भी देखना होगा। जैसा कि लेनिन ने निर्दिष्ट किया है : **''..कोई पार्टी वास्तव में मजदूरों की राजनीतिक पार्टी है या नहीं, यह सिर्फ मजदूरों की सदस्यता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उन लोगों पर भी निर्भर करता है जो इसे नेतृत्व देते हैं, और इसकी कार्रवाइयों तथा इसके राजनीतिक रणकौशल की अन्तर्वस्तु पर भी निर्भर करता है। सिर्फ यह परवर्ती चीज ही तय करती है कि क्या हमारे सामने वास्तव में सर्वहारा वर्ग की एक राजनीतिक पार्टी मौजूद है।''** एक सच्ची सर्वहारा राजनीतिक पार्टी की सोच मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्त से मार्गनिर्देशित होनी चाहिए—केवल तभी वह समाज के विकास के नियमों पर पकड़ कायम कर सकेगी और अपने लिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी लाइन का निर्धारण कर सकेगी तथा ऐसा हरावल बन सकेगी जो वर्ग-शत्रु के विरुद्ध संघर्ष में सर्वहारा वर्ग और क्रान्तिकारी जनता का मार्गदर्शन करे और विजय की मंजिल तक उनका नेतृत्व करे। यदि वह कभी भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद से विचलित होती है, यानी, यदि यह सर्वहारा वर्ग के साथ विश्वासघात करती है, तो चाहे यह जिन किन्हीं भी वर्ग-हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करे, चाहे यह अपना जो भी नाम रख ले, चाहे इसका संघटन जैसा भी हो, यह किसी भी अर्थ में एक सर्वहारा राजनीतिक पार्टी नहीं बनी रह सकती है और सर्वहारा वर्ग का हरावल दस्ता तो कतई नहीं हो सकती है। इसके विपरीत, यह एक बुर्जुआ राजनीतिक पार्टी है, एक संशोधनवादी पार्टी है। सोवियत गद्दार संशोधनवादियों का गिरोह मार्क्सवाद-लेनिनवाद के साथ पूरीतरह विश्वासघात कर चुका है, और हालांकि अभी भी उन्होंने ''कम्युनिस्ट पार्टी'' का साइनबोर्ड टांग रखा है, लेकिन वास्तव में उनकी पार्टी एक संशोधनवादी पार्टी, एक फासिस्ट पार्टी बन चुकी है, जो एक नये नौकरशाह इजारेदार बुर्जुआ वर्ग के हितों की सेवा करती है।

इसके अतिरिक्त, हमारी पार्टी इसलिए सर्वहारा वर्ग का हरावल है क्योंकि इसका एक सख्त संगठन है और सख्त अनुशासन है। यह सर्वहारा वर्ग का अग्रिम दस्ता है, और साथ ही, एक संगठित दस्ता है। इसके भीतर संगठन का ऊंचे स्तर का बोध है और एक फौलादी अनुशासन है—पार्टी के हर सदस्य के लिए इसके किसी एक संगठन में होना और वहां कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करना अनिवार्य है, उन्हें एक संगठित एवं अनुशासित समूह के गठन के लिए, एक अत्यधिक केन्द्रीकृत लड़ाकू दस्ते के गठन के लिए पार्टी के निर्देशों को लागू करना होता है। इसी सख्त संगठन और अनुशासन का नतीजा है कि हमारी पार्टी सही लाइन का अमल सुनिश्चित कर पाने में, और इसलिए एक शक्तिशाली शत्रु पर विजय हासिल करने में तथा क्रान्ति को शानदार जीत की मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब हुई है।

''चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक पार्टी, सर्वहारा वर्ग का हरावल है।'' संविधान का यह उद्धरण हमारी पार्टी के चरित्र को, सर्वहारा वर्ग के साथ इसके सम्बन्ध को और पार्टी और वर्ग के बीच के फर्क को सही ढंग से अभिव्यक्त करता है। हमारी पार्टी को सर्वहारा वर्ग से जो चीज जोड़ता है, वह इसके वर्ग-चरित्र का निर्धारण करती है : सर्वहारा वर्ग पार्टी का वर्ग-आधार है; जो चीज हमारी पार्टी को सर्वहारा वर्ग से अलग करती है वह इसके अग्रिम (या उन्नत) चरित्र का निर्धारण करती है : यह सर्वहारा वर्ग का हरावल दस्ता है। जब तक वर्ग और राजनीतिक पार्टियां मौजूद रहेंगी तबतक सर्वहारा वर्ग के हिरावल और उसके अन्य संगठनों के बीच के अन्तर समाप्त नहीं हो सकते, तब तक, जो पार्टी के सदस्य हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच के अंतर समाप्त नहीं हो सकते। इन अंतरों से इनकार करना पार्टी संगठनों के अग्रिम चरित्र को छोटा करके देखना होगा; पार्टी-सदस्यों की अनुकरणीय हरावल भूमिका को कम करके देखना होगा। लेकिन इन अन्तरों को अलग-थलग रखकर देखने का सवाल नहीं है। यदि पार्टी अपने को वर्ग से और अन्य क्रान्तिकारी जनसंगठनों से अलग कर लेती है, यदि इसके सदस्य अपने को गैर-पार्टी जनसमुदाय से अलग कर लेते हैं, तो यह सर्वहारा वर्ग के हरावल के रूप में पार्टी के चरित्र को भी समाप्त कर सकता है और सर्वहारा वर्ग के अग्रिम (या उन्नत) तत्वों के रूप में इसके सदस्यों की भूमिका भी खतम हो सकती है। ऐसी स्थिति में, पार्टी एक सर्वहारा राजनीतिक पार्टी नहीं बनी रह पायेगी।

अध्यक्ष माओ इस बारे में हमें जो शिक्षा देते हैं, वह यह है : **''पार्टी सर्वहारा वर्ग का हरावल है और सर्वहारा संगठन का उच्चतम रूप है। इसे सभी अन्य संगठनों को, जैसे कि सेना, सरकार और जनसंगठनों को नेतृत्व देना चाहिए।''** पार्टी को सर्वहारा वर्ग के सभी संगठनों को नेतृत्व देना चाहिए और जबतक यह ऐसा नहीं करेगी, सर्वहारा वर्ग का संघर्ष विजयी नहीं हो सकता।

विजय के लिए संघर्ष छेड़ने के लिए, सर्वहारा वर्ग को सिर्फ एक क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टी स्थापित करने की ही आवश्यकता नहीं होती, इसे वे सभी संगठन खुद को मुहैया कराने होंगे जो सफलतापूर्वक क्रान्तिकारी संघर्ष शुरू करने के लिए आवश्यक हैं : इनमें राजकीय निकाय, सैनिक मामलों का विभाग, ट्रेड यूनियनें, गरीब किसानों के संगठन, स्त्रियों के संघ, युवा लीग, लाल गार्ड, नन्हें लाल गार्ड और क्रान्तिकारी जन समुदाय के अन्य संगठन शामिल हैं। ये विभिन्न विभाग और संगठन, समाजवादी क्रान्ति और निर्माण के लिए, सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के लिए, कम्युनिज्म को हासिल करने के लिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं; इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये विभाग और ये संगठन सर्वहारा वर्ग और व्यापक क्रान्तिकारी जन-समुदाय की गोलबन्दी को सम्भव बनाते हैं तथा सभी मोर्चों पर सर्वहारा पोजीशन को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए, समाजवाद के लक्ष्य की सेवा के लिए, यह जरूरी है कि सभी क्रान्तिकारी संगठनों को अपनी भूमिका पूरी तरह निभाने लायक बनाया जाये। लेकिन एक सही दिशा के साथ यह सक्रिय भूमिका वे तब तक नहीं निभा सकते जब तक कि वे एक पार्टी के नेतृत्व के अन्तर्गत, इसकी मार्क्सवादी-लेनिनवादी लाइन के मार्गदर्शन में काम न करते हों।

पार्टी के नेतृत्व को मजबूत बनाकर ही सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व के सुदृढ़ीकरण और समाजवाद के लक्ष्य को जीत की मंजिल तक पहुंचाने की मूलभूत गारण्टी हासिल की जा सकती है। सर्वहारा वर्ग के क्रान्तिकारी संगठनों को पार्टी के केन्द्रीकृत नेतृत्व के अन्तर्गत काम करना होता है, वे अपनी ठोस परिस्थितियों को उससे पार्टी के नेतृत्व से) स्वतंत्र होकर काम करने के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि पार्टी उन्हें नेतृत्व नहीं प्रदान करती, या यदि वे पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, तो ये संगठन अपनी दिशा खो बैठने और बुर्जुआ वर्ग द्वारा ठग लिये जाने, नियोजित किये जाने तथा इस्तेमाल किये जाने का खतरा मोल लेते हैं। बुर्जुआ और संशोधनवादी चिन्तन-प्रवृत्तियों के भ्रष्टकारी प्रभाव के अन्तर्गत, वे बुर्जुआ वर्ग के राजनीतिक पुछल्ले बन सकते हैं, और यहां तक कि सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध बुर्जुआ वर्ग के उपकरणों में तब्दील किये जा सकते हैं। यही कारण हैं कि जो लोग पार्टी के नेतृत्व को अस्वीकार करते हैं, वे वस्तुतः स्वयं को बुर्जुआ वर्ग के पक्ष में, और सर्वहारा वर्ग के विरोध में खड़ा करते हैं; वे लोग सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को कमजोर कर रहे हैं और उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

पार्टी सर्वहारा वर्ग के संगठन का उच्चतम रूप है और इसे सभी चीजों में नेतृत्व लागू करना चाहिए, यह पार्टी-निर्माण विषयक मार्क्सवादी सिद्धान्त का एक बुनियादी उसूल है। पार्टी और जनता के अन्य संगठनों के बीच का रिश्ता, नेतृत्व देने वाले और नेतृत्व में काम करने वाले के बीच का (या नेता और मातहत के बीच का) रिश्ता होता है। सर्वहारा राजनीतिक पार्टी की प्रकृति और उसके कार्यभारों से ही उसकी नेतृत्वकारी पोजीशन और भूमिका का निर्धारण होता है, सर्वहारा वर्ग के बुनियादी हितों का तकाजा होता है कि पार्टी अपनी यह भूमिका निभाये—यह एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी सत्य है जिसे क्रान्तिकारी संघर्ष ने बार-बार प्रदर्शित किया है।

पार्टी के सर्वहारा चरित्र को बनाये रखने के लिए संघर्ष करो

पार्टी के भीतर इसके चरित्र के प्रश्न पर दो लाइनों का संघर्ष हमेशा ही बहुत तीखा रहा है। अवसरवादी लाइनों के सभी नेता सर्वहारा क्रान्ति को क्षतिग्रस्त करने के अपने आपराधिक उद्देश्य की पूर्ति के उद्देश्य से सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक पार्टी को चरित्र को विकृत बनाने के लिए हमेशा ही हर तरह से कोशिशें करते रहे हैं। अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में, पुराने संशोधनवादियों ने, बर्नस्टीन और काउत्स्की ने, सभी किस्म की बेतुकी बातें फैलाईं और सर्वहारा पार्टी को एक सुधारवादी पार्टी, एक अवसरवादी और संशोधनवादी पार्टी में बदल डालने की हर कोशिश की। वे दूसरे इण्टरनेशनल के पतन के कारण बने। आधुनिक संशोधनवादी—ख्रुश्चोव-ब्रेझनेव एण्ड कं. —एक बार फिर अतीत के संशोधनवादियों के चीथड़े पहनकर ''समूची जनता की पार्टी'' के बारे में अपनी तमाम अनर्गल बकवास पर दांव लगा रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि ''मजदूर वर्ग की पार्टी अब सोवियत जनता के हरावल में बदल चुकी है; यह अब समूची जनता की पार्टी बन चुकी है'' और ''समूची जनता का राजनीतिक संगठन है।'' जैसा कि हर कोई जानता है, उन्होंने सर्वहारा राजनीतिक पार्टी के चरित्र को विकृत कर दिया है, उन्होंने लेनिन द्वारा स्थापित सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी को एक संशोधनवादी पार्टी में, एक फासिस्ट पार्टी में बदल डाला है। अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए यह एक अत्यन्त गम्भीर सबक है। हमारी पार्टी में भी पार्टी के चरित्र के प्रश्न पर तीखा संघर्ष मौजूद रहा है। मजदूर वर्ग के ठग और गद्दार ल्यू शाओ-ची ने इस विचार को फैलने की हर चन्द कोशिश की कि ''पार्टी जन समुदाय की पार्टी है, जनता की पार्टी है'' और इसतरह उसने पार्टी के चरित्र को विकृत करने की कोशिश की। कैरियरवादी, षड्यंत्रकारी, दुरंगी चाल चलने वाले प्रतिक्रान्तिकारी, और देश के गद्दार लिन प्याओ ने भी पार्टी की बुनियादी लाइन और कार्यक्रम में हेरफेर करने की कोशिश के रूप में इसीतरह के प्रयास किये। तथाकथित कम्युनिज्म के एक घटिया ब्राण्ड को बढ़ावा देकर उसने हमारी मार्क्सवादी पार्टी को एक संशोधनवादी पार्टी में, प्रतिक्रान्तिकारी पुनर्स्थापना के एक उपकरण में बदल डालने की उम्मीद की थी। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति ने और लिन प्याओ की आलोचना करने तथा कार्यशैली में सुधार करने के आन्दोलन ने, जिसे व्यक्तिगत तौर पर अध्यक्ष माओ ने शुरुआत किया था और नेतृत्व दिया था, हमारी पार्टी की प्रकृति को बदल डालने और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना कर देने के ल्यू शाओ-ची और लिन प्याओ के आपराधिक षड्यंत्र को पूरीतरह कुचल डाला। हमारी पार्टी शुद्धीकृत होकर, पहले हमेशा की अपेक्षा अधिक ठोस और अधिक ऊर्जस्वी होकर इस संकट से बाहर आई। पार्टी के भीतर दो लाइनों के बीच का संघर्ष गहराई के साथ दिखलाता है कि पार्टी के चरित्र की सुरक्षा करना अत्यधिक महत्व का विषय है। यह पार्टी और राज्य की नियति के साथ, और इस प्रश्न के साथ अंतरंगता के साथ जुड़ा हुआ है कि क्रान्ति विजय हासिल करेगी या पराजय के गर्त में चली जायेगी। हमारी पार्टी का सतत निर्माण करते रहना, पार्टी के चरित्र को विकृत करने के संशोधनवादियों के षड्यंत्रों का मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुङ विचारधारा का इस्तेमाल करते हुए भण्डाफोड़ करते रहना और उन्हें नाकाम करते रहना—इसी से यह गारण्टी हासिल होगी कि हमारी पार्टी अपना सर्वहारा चरित्र हमेशा बनाये रखेगी।

एक कम्युनिस्ट के लिए, पार्टी के सर्वहारा चरित्र को बनाये रखने के संघर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज यह है कि वह अपनी सर्वहारा पार्टी-स्पिरिट को मजबूत बनाये। हमें यह समझना होगा कि एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी का निर्माण और इसके सर्वहारा चरित्र को ऊंचा उठाना इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यभार है। पार्टी एक जीवन्त जैविक संघटन (लिविंग ऑर्गनिज्म) के सदृश होती है, और इसके सदस्यों की विशाल संख्या बहुत सारी कोशिकाओं के समान होती है, जिनमें से प्रत्येक उस जैविक संघटन का अंग होती है। प्रत्येक सदस्य में पार्टी-स्पिरिट जितनी ही मजबूत होगी, वर्ग-संघर्ष और दो लाइनों के संघर्ष की उसकी चेतना जितनी ही ऊंची होगी, उतने ही बेहतर ढंग से वह अपनी अनुकरणीय भूमिका का निर्वाह कर सकेगा, तथा उतने ही बेहतर ढंग से पार्टी के सर्वहारा चरित्र की हिफाजत की जा सकेगी। अपनी सर्वहारा पार्टी-स्पिरिट को मजबूत बनाने के लिए, एक कम्युनिस्ट को मनोयोग के साथ पढ़ना और अध्ययन करना चाहिए तथा मार्क्सवादी पोजीशन, दृष्टिकोण एवं पद्धति की समझ कायम करने के लिए जूझना चाहिए। उसे सिद्धान्त और व्यवहार को जोड़ने में, सही और गलत लाइन के बीच फर्क करने में, तथा असली मार्क्सवाद को नकली से अलग कर पाने की अपनी क्षमता को मजबूत बनाने में सक्षम होना चाहिए। उसे पार्टी की बुनियादी लाइन और ''तीन करने योग्य और तीन न करने योग्य चीजों'' का सिद्धान्त हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। उसमें गलत लाइनों और रुझानों के विरुद्ध निर्मम संघर्ष छेड़ने का साहस होना चाहिए। ऐसा करने के लिए, उसे तीन महान क्रान्तिकारी आन्दोलनों के व्यवहार के मैदान में सक्रियतापूर्वक कूद पड़ना चाहिए, पार्टी के साथ विचारधारात्मक स्तर पर एकरूप हो जाने के उद्देश्य से अपने विश्व-दृष्टिकोण को बदल

(पेज 2 पर जारी)

जनमुक्ति की अमर गाथा : चीनी क्रान्ति की सचित्र कथा (भाग-ग्यारह)

'महान अग्रवर्ती छलांग' और उसके बाद

1. 1958 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 'महान अग्रवर्ती छलांग' के रूप में समाजवादी रूपान्तरण की अगली, नई, फैसलाकुन दौर की शुरुआत की, जिसने चीन के व्यापक देहाती इलाके में उत्पादन, प्रशासन, रहन-सहन और चेतना को बुनियादी रूप से बदल डाला। चीन के देहाती इलाके में प्रशासन की बुनियादी इकाई काउण्टी (गांव) या कस्बा होते हैं।

'महान अग्रवर्ती छलांग' के दौरान प्रशासन और उत्पादन की बुनियादी इकाई के रूप में जन कम्यूनों की स्थापना हुई जो एक सर्वथा नये किस्म की समाजवादी संस्था थी। पूरे गांव की सभी सहकारी इकाइयों ने मिलकर इस नई आर्थिक-राजनीतिक इकाई का निर्माण किया। जन कम्यूनों का निर्माण सरकार और किसानों के बीच के अन्तर को मिटाने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। इन कम्यूनों में किसान उत्पादन के साथ ही प्रबन्धन और प्रशासन विषयक सभी फैसले भी खुद ही लेने लगे। अभी भी बुनियादी इकाई के रूप में लगभग बीस परिवारों को लेकर बनायी गयी उत्पादन टीमें मौजूद थीं लेकिन इन टीमों को लेकर एक व्यापक संगठन बना दिये जाने के बाद गोत्र, बिरादरी आदि की विभाजक दीवारें समाप्त हो गईं। किसानों की सक्रिय पहलकदमी, भागीदारी और व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और छोटे बांध, सड़कें एवं ग्रामीण-स्तर पर उद्योगों की योजनायें बड़े स्तर पर बनाई जाने लगीं।

माओ का लगातार इस बात पर जोर था कि सही मायने में समतामूलक समाज बनाने के लिए गांव और शहर के बीच तथा किसान और मजदूर के बीच का अंतर लगातार कम करते जाना बेहद जरूरी है। साथ ही, शासन का काम धीरे-धीरे, बुनियादी स्तर पर सीधे जनता को सौंपा जाना चाहिए और केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण में सही तालमेल होना चाहिए। जन-कम्यूनों की स्थापना के बाद शहरों की ही तरह गांवों में भी अस्पतालों, स्कूलों और नये उद्योगों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ और देहात में भी शहरी जीवन की तरह की सुविधाएं मुहैया की जाने लगीं।

जन कम्यूनों के बिना गांवों में उद्योगों का विकास सम्भव नहीं हो पाता। पूरे देश में गांवों में स्त्रियों-पुरुषों को प्रोत्साहित किया गया कि वे जनता की जरूरतों की पूर्ति और जीवन-स्तर में तरक्की के लिए नये-नये रास्ते निकालें और नये-नये कारखाने लगायें। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन और नेतृत्व किया और सरकार ने देश की समग्र आर्थिक योजना के हिसाब से इसमें मदद की, लेकिन बुनियादी तौर पर सबकुछ लोगों की अपनी कोशिशों और पहलकदमी पर निर्भर था।

3. देहाती क्षेत्रों की अपनी यात्रा के दौरान एक किसान से बातचीत करते हुए माओ, 1958

5. सुप्रसिद्ध लेखक लाओ श और पीकिङ ऑपेरा के अभिनेता मेइ लान फाङ के साथ माओ, 1960

1. माओ, चीनी नौजवान संघ के तीसरे सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ, 1957

4. हुनान प्रान्त में अपने जन्मस्थान शाओशान गांव में एक किसान परिवार से बातचीत करते हुए माओ, 1959

6. 'महान अग्रवर्ती छलांग' के दौर का एक जन-प्रदर्शन। तीन बड़े लाल बैनरों पर लिखा है : 'आम लाइन', 'महान अग्रवर्ती छलांग' और 'जन-कम्यून'

2. पीकिङ के निकट एक निर्माण कार्य में शारीरिक श्रम करते हुए माओ, 1958

2. 'महान अग्रवर्ती छलांग' ने बहुतेरी समस्याओं को हल किया और महान उपलब्धियां हासिल कीं। लेकिन इसी दौरान देश को कई अभूतपूर्व संकटों-समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे गम्भीर अड़चनें भी पैदा हो गईं। तीन वर्षों तक लगातार भयंकर सूखा पड़ा। इसी बीच चीनी अर्थतंत्र को ध्वस्त करने की मंशा से सोवियत संघ के नये संशोधनवादी शासकों ने अचानक हर तरह की तकनीकी-आर्थिक मदद बंद कर दी और अपने सभी विशेषज्ञों को वापस बुला लिया। सोवियत शासकों की नई पूंजीवादी नीतियों की चीन की पार्टी जो आलोचना कर रही थी, उसे बन्द करने और बदले की कार्रवाई के तौर पर ख्रुश्चोव की सरकार ने यह कदम उठाया था, लेकिन यह भी नाकाम रहा। चीनी पार्टी के भीतर भी, ल्यू शाओ-ची, देङ सियाओ-पिङ और जो दूसरे भितरघाती पूंजीवादी पथगामी थे, वे कठिनाइयों, प्रतिकूल परिस्थितियों और उत्पादन में निर्धारित लक्ष्य पूरा न हो पाने का रोना रोते हुए यह तर्क दे रहे थे कि हमें अपना रास्ता बदल देना चाहिए। उनका कहना था कि क्रान्ति को आगे बढ़ाने के काम में फंसकर मेहनतकश जनता अपने असली काम—उत्पादन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। उनका कहना था कि शासन कैसे चलाया जाये, या औद्योगिक एवं कृषि उपक्रमों को कैसे संगठित किया जाये और चलाया जाये, या लोगों का श्रम धीरे-धीरे पूरी जनता की क्षमताओं को मुक्त करने का काम कर रहा है या नहीं, या पूरा समाज किस दिशा में आगे जा रहा है—यह देखना आम लोगों का काम नहीं है, बल्कि यह पार्टी और सरकार का काम है।

माओ और उनके पक्ष में खड़े पार्टी के दूसरे हिस्से ने उपरोक्त संशोधनवादी विचार का जोरदार विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद के अन्तर्गत, नये उत्पादन-सम्बन्धों के विकास के साथ चेतना के उन्नत होते जाने के साथ ही, बुनियादी इकाइयों से शुरू करके, शासन चलाने में जनता की भागीदारी बढ़ती रहनी चाहिए। तभी जाकर समाजवादी जनतंत्र का व्यापक आधार तैयार हो सकेगा, गांव और शहर के बीच किसान और मजदूर के बीच का तथा मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच के अन्तर धीरे-धीरे कम हो सकेंगे, जनता की पहलकदमी और सर्जनात्मकता उन्नत हो सकेगी, नौकरशाही, फरमानशाही, भ्रष्टाचार और विशेषाधिकारों की प्रवृत्तियों पर रोक लग सकेगी और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना को रोकना सम्भव हो सकेगा।

कुल मिलाकर, यह दो लाइनों के बीच का वही संघर्ष था जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं कांग्रेस

3. 1957 में दक्षिणपंथियों के खिलाफ चलाये गये संघर्ष से लेकर 1959 की लूशान मीटिंग में फङ-त-हुवाई के पार्टी-विरोधी गुट के विरुद्ध संघर्ष तक, हर मुद्दे पर संघर्ष का मुख्य केन्द्र बिन्दु यही था कि समाजवादी क्रान्ति को वर्ग-संघर्ष के जरिये आगे बढ़ाया जाये या पूंजीवाद के रास्ते पर आगे बढ़ा जाये।

उधर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन में भी संशोधनवाद के विरुद्ध संघर्ष तीखा होता जा रहा था। 1960 में 'लेनिनवाद जिन्दाबाद' शीर्षक निबन्ध लिखकर चीन की पार्टी ने ख्रुश्चोवी संशोधनवाद के विरुद्ध संघर्ष को और तेज कर दिया। ख्रुश्चोवी गुट को समझाने-बुझाने की नाकाम कोशिशों के बाद चीनी पार्टी को कुछ समय तक यह आशा थी कि सोवियत संघ की पार्टी के भीतर से भी ख्रुश्चोवी नीतियों का तीखा विरोध होगा। लेकिन वहां वर्ग-शक्ति-संतुलन पूरी तरह उलट चुका था और नये बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधि छल-छद्म-षड्यंत्र से पूरी तरह राज्यसत्ता और पार्टी पर काबिज हो चुके थे। तब चीन की पार्टी ने संघर्ष को तीखा कर दिया जिसका फैसलाकुन मुकाम 1963 में 'महान बहस' के रूप में सामने आया। 'महान बहस' के दस्तावेजों में चीन की पार्टी ने सिलसिलेवार ख्रुश्चेव के 'शान्तिपूर्ण संक्रमण, शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व' के सिद्धान्तों और 'समूची जनता की पार्टी' और 'समस्त जनगण के राज्य' जैसी स्थापनाओं की असलियत उजागर करते हुए यह सिद्ध किया कि वर्ग संघर्ष और सर्वहारा अधिनायकत्व के बुनियादी उसूलों को छोड़कर ख्रुश्चोव पूरी तरह नकली कम्युनिज्म का मसीहा बन चुका है तथा सोवियत संघ में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो चुकी है।

7. मिङ मकबरा बांध के निर्माण में लगभग 50,000 मजदूरों ने भाग लिया। 1958-59

8. शिउ शिन कम्यून की स्त्रियां अपनी बंदूकें रखकर खेतों पर काम में जुटी हुईं। 'महान अग्रवर्ती छलांग' के दौरान

9. पीकिङ में 'कम्युनिस्ट यूथ लीग' की नवीं कांग्रेस के छात्र प्रतिनिधियों के साथ माओ, 1964

(पेज 8-9 पर जारी)

जनमुक्ति की अमर गाथा : चीनी क्रान्ति की सचित्र कथा (भाग-ग्यारह)

10. महान अग्रवर्ती छलांग के दौर का एक पोस्टर : ''1961 की आम दिशा जिन्दाबाद!''

4. जनवरी, 1962 में केन्द्रीय कमेटी की कार्यकारी बैठक में माओ ने संशोधनवाद के खतरे के विरुद्ध सतर्कता पर विशेष जोर दिया ओर उसी वर्ष पैताएहो में हुई केन्द्रीय कमेटी की कार्यकारी बैठक में तथा सितम्बर में हुई केन्द्रीय कमेटी के दसवें पूर्ण अधिवेशन में उन्होंने पहली बार समाजवाद के पूरे ऐतिहासिक काल के बुनियादी गुणों-लक्षणों का तफसील से उल्लेख करते हुए इस पूरे काल के लिए पार्टी की बुनियादी लाइन पेश की।

सोवियत संघ और चीन के अनुभवों का अध्ययन करने के बाद माओ और अन्य चीनी क्रान्तिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि समाजवाद परस्पर शत्रु वर्गों के बीच संघर्ष का अंत नहीं करता। बल्कि, पुराने शासक वर्गों के खात्मे के बाद संघर्ष का क्षेत्र हटकर स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर आ जाता है। पार्टी में परस्पर-विरोधी नीतियों और रणनीतियों—भिन्न रास्तों के बीच का संघर्ष वास्तव में परस्पर-विरोधी वर्गों के बीच के संघर्ष का ही प्रतिनिधित्व करता है। किसान-मजदूर और उनके सही पार्टी नेता समाजवादी रास्ते पर चलना चाहते हैं। यानी, पुराने समाज के अवशेष के रूप में कायम सामाजिक अन्तरों-असमानताओं और पुराने विचारों का निर्मूलन, पूरी दुनिया में क्रान्तियों का समर्थन और पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश को एक आधार क्षेत्र बना देना। दूसरी ओर, पार्टी के ही वे नेता और उनके अनुगामी होते हैं, जो पुराने असमानतापूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखना चाहते हैं और समाजवादी देश को साम्राज्यवादी विश्व-व्यवस्था का अंग बना देना चाहते हैं। ऐसे लोगों की नीतियां समाजवाद के अंतर्गत नये बुर्जुआ वर्ग, नये विशेषाधिकारों और नई असमानताओं को जन्म देती हैं और समाजवाद वस्तुतः राजकीय इजारेदार पूंजीवाद बनकर रह जाता है। इन संशोधनवादियों को पुराने सामाजिक सम्बन्धों के अवशेषों से, पुरानी परम्पराओं से और जनता के बीच मौजूद पुरानी संस्कृति एवं आदतों से बल मिलता है। साथ ही, विश्व स्तर पर कायम पूंजीवादी व्यवस्था भी प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से इनकी मदद करती है।

13. द्वितीय राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने आये तिब्बत के प्रतिनिधियों के साथ माओ, 1960

11. वियतनामी क्रान्ति के नेता और वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के साथ माओ, 1964

14. किंडरगार्टन में पढ़ते बच्चे। माओ के चित्र के नीचे पोस्टर पर लिखा है : 'समाजवादी चेतना से लैस सुसंस्कृत श्रमिक बनने के लिए स्वयं को शिक्षित करो'

12. छाङ च्याङ नदी में तैरते हुए माओ, ऊहान, 1961

15. विख्यात वैज्ञानिक ली सिग्वाङ के साथ माओ, 1964

'महान अग्रवर्ती छलांग' और उसके बाद

16. एक पोस्टर : ''महान अग्रवर्ती छलांग के युद्ध के नगाड़े को और तेज करो'', 1959

5. माओ त्से-तुङ ने समाजवादी संक्रमण के दौरान जारी वर्ग-संघर्ष की दीर्घकालिक प्रकृति, अन्तरविरोधों के स्वरूप और लगातार मौजूद पूंजीवादी पुनर्स्थापना के खतरों की चर्चा करते हुए समाजबादी शिक्षा के आन्दोलन पर विशेष जोर दिया और इस तरह अधिरचना के महत्व को रेखांकित किया। मई, 1963 में माओ के निर्देशन में तैयार किये गये 'दस सूत्री फैसले' में समाजवादी शिक्षा आन्दोलन के बारे में पार्टी की लाइन, उसूल और नीतियां निर्धारित की गईं। माओ ने साफ-साफ बताया कि अगर हम वर्ग संघर्ष और सर्वहारा अधिनायकत्व को भूल गये तो ''लाजिमी तौर पर प्रतिक्रान्तिकारी पुनर्स्थापना होने में, मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी के अनिवार्य रूप से एक संशोधनवादी पार्टी या एक फासीवादी पार्टी बनने में तथा समूचे चीन का राजनीतिक रंग बदलने में, ज्यादा समय नहीं लगेगा ...।'' माओ ने 1963 में महान बहस के दौरान प्रस्तुत विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन की आम दिशा सम्बन्धी दस्तावेज में, एक बार फिर, पूंजीवादी पुनर्स्थापना रोकने के लिए समाजवादी समाज में वर्ग संघर्ष को जारी रखना अनिवार्य बताया।

17. कोरियाई वर्कर्स पार्टी के सेक्रेटरी और जनवादी कोरिया गणराज्य के अध्यक्ष किम इल-सुङ के साथ माओ।

6. 1964 में शुरू हुआ 'महान समाजवादी शिक्षा आन्दोलन' वास्तव में चीन की ऐतिहासिक 'सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति' (1966-76) की भूमिका थी। माओ ने इस दौरान पहली बार ठोस रूप में बताया कि ''वर्तमान आन्दोलन में प्रहार के मुख्य लक्ष्य पार्टी के वे सत्ताधारी लोग हैं जो पूंजीवादी रास्ता अपना रहे हैं।'' 'महान समाजवादी शिक्षा आन्दोलन' के दौरान, राजनीति और शिक्षा के साथ ही साहित्य-कला-संस्कृति के क्षेत्र में भी पूंजीवादी विचारों-नीतियों के विरुद्ध संघर्ष तीखा होता चला गा। जिसकी एक नई, उन्नत मंजिल 1966 में शुरू हुई 'महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति' लगातार रेखांकित की गयी समाजवाद की बुनियादी समस्याओं का ठोस, स्पष्ट और व्यापक समाधान प्रस्तुत करने वाली पहली कोशिश थी। यह एक सर्वतोमुखी महान राजनीतिक क्रान्ति थी। इस दौरान, माओ ने पहली बार सर्वहारा वर्ग को अधिरचना के क्षेत्र में वर्ग-संघर्ष चलाने के रास्ते से, एक चौतरफा सुनियोजित क्रान्ति को सतत् क्रान्ति के जरिये हल करके कम्युनिज्म की ओर संक्रमण को सुनिश्चित करने की कुंजी प्रदान की। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सर्वहारा अधिनायकत्व कायम होने के बावजूद राज्यसत्ता और पार्टी में बैठे जो पूंजीवादी पथगामी समाजवाद की राह में रोड़े बने हुए थे, पहली बार उनकी स्पष्ट पहचान कायम करके, करोड़ों जनसमुदाय को जागृत करके बुर्जुआ हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने के लिए उनका आह्वान किया गया।

18. डा. सुनयात सन की विधवा सुङ चिङ लिङ के साथ माओ शंघाई में उनके पुराने निवास स्थान पर, 1961

19. प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान डब्ल्यू. ई.बी. दूबोई और प्रगतिशील अमेरिकी लेखिका अन्ना लुई स्ट्रांग के साथ ऊहान में माओ, 1959

अगले अंक में पढ़िए :

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति

भूकम्प : खून सने हाथों को साफ नहीं किया जा सकता

(पेज 1 से आगे)

जमात विनाशलीला के बीच भी रासलीला रचाने में पीछे नहीं है। ठीक 26 जनवरी के दिन जिस दिन भूकम्प आया, समाजवादी पार्टी के महासचिव अमरसिंह के जन्मदिन की पार्टी राजधानी दिल्ली के इण्टरकांटीनेन्टल होटल में मनाई गयी, जिसमें प्रधानमंत्री के दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य और उनकी पत्नी, पद्मभूषण डाक्अर त्रेहन, गरीबों के मसीहा मुलायम सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला व उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, पद्मश्री अमिताभ बच्चन, रवीना टंडन, जीनत अमान, उद्योगपति अनिल अम्बानी सहित अनेक हस्तियां शामिल हुईं। केक काटा गया, रात भर नाच-गाना हुआ और छककर दारू पी गयी। यह पार्टी अगले दिन भी होटल ताज पैलेस में जारी रही। रोम के जलने पर एक नीरो बांसुरी बजा रहा था। यहां तो नीरो जैसों की पूरी जमात है। ऐसे में भूकम्प से राहत और बचाव की सुधि भला कैसे हो सकती है।

इस बारे में अब तक तमाम रिपोर्टें आ चुकी हैं कि किस तरह भूकम्प के पुराने तर्जुबों और वैज्ञानिकों द्वारा दी गयी चेतावनियों पर सरकारें आंखें मूंदी रहीं। न तो कोई दूरगामी रणनीति बनायी गयी न ही फौरी राहत का कोई इन्तजाम ही किया गया। उत्तरकाशी और महाराष्ट्र के लातूर में भूकम्प से हुई तबाही के बाद भी आने वाली तबाही का मुकाबला करने की कोई तैयारी नहीं थी। यह जानकारी सरकारी अमले के पास पहले से मौजूद थी कि गुजरात का समूचा कच्छ क्षेत्र तेज भूकम्प की सम्भावना वाले क्षेत्रों में आता है। 26 जनवरी से कुछ दिन पहले ही कच्छ क्षेत्र में भूकम्प के कुछ हल्के झटके महसूस किये गये थे। इसकी जानकारी भी मौसम विज्ञान विभाग ने सरकार को दी थी। लेकिन अपने चरित्र के अनुसार सरकारें आंख-कान बन्द किये रोजमर्रा के लूटपाट के धंधों में लगी रहीं।

भूकम्प आने के बाद सरकारी राहत और बचाव कार्य का जो आलम रहा उसने पूंजीवादी शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता और नाकारेपन को इस कदर नंगा करके रख दिया है कि किसी तरह की पर्देदारी बेहया लाजबचाऊ कोशिश ही हो सकती थी। हालत यह थी कि सरकार के पास मलबे में फंसे लोगों की पहचान करने, पत्थरों को काटने और मलबा हटाने के कारगर औजार तक मौजूद नहीं थे। भ्रष्ट विलासी नौकरशाही की काहिली और लालफीताशाही से होने वाली देरी का आलम यह था कि कई विदेशी राहत और बचाव दल सरकारी दलों से पहले पहुंचकर अपना काम शुरू कर चुके थे। परमाणु परीक्षणों और संचार क्रान्ति के दम पर दुनिया की महाशक्ति बनने की डींग हांकने वाली घनघोर "राष्ट्रवादी" सरकारों की कार्यकुशलता का आलम यह था कि दिल्ली और अहमदाबाद में आपदा प्रबन्धन दल लगभग एक हफ्ते बाद ढंग से काम करना शुरू कर सका। राहत और बचाव कार्यों में कोई तालमेल नहीं था।

संचार व्यवस्था इतनी फिसड्डी साबित हुई कि भूकम्प आने के तीन बाद तक भी इसका ठीक-ठीक अनुमान दिल्ली के सरकारी हलकों तक नहीं पहुंच पा रहा था कि कितनी तबाही मची है। प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री मरने वालों की संख्या को लेकर बेशर्म बयानबाजियों में उलझे रहे। दिल्ली दरबार को सबसे अधिक चिन्ता इस बात की थी कि विदेशों से आने वाली राहत सामग्री का समन्वय कैसे किया जाये। सत्ताधारी हिन्दुत्व के ठेकेदार राहत में मिलने वाली नकदी पर आंखें गड़ाये रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने तो यहां तक कह डाला कि लोग राहत के रूप में नकदी ही दें क्योंकि सम्पन्न गुजरात को खाद्य सामग्री और कपड़ों की जरूरत नहीं है।

अहमदाबाद और कच्छ जिले के मुख्यालय भुज में सबसे ज्यादा तबाही भवन-निर्माण मानदण्डों की धज्जियां उड़ाते हुए बनायी गयी बहुमंजिला इमारतों से हुई है। बिल्डरों ने पैसा बनाने के लिए घटिया सामान लगाये और मिट्टी की मजबूती-कमजोरी का ख्याल किये बिना इमारतों की इतनी कमजोर बुनियाद बनायी थी कि भूकम्प के झटकों से वे बालू की भीत की तरह भरभराकर गिर पड़ीं। जनता के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने कई ऐसे बिल्डरों को गिरफ्तार कर समूचे सत्ता तंत्र के दामन के दाग छिपाने की कोशिश की है। लेकिन कौन नहीं जानता कि बिल्डर सिर्फ अपने बूते यह अंधेरगर्दी नहीं कर सकते थे। गिरफ्तार किन-किन बिल्डरों को गुजरात के सत्ताधारी किन-किन "राष्ट्रवादी" मंत्रियों-पार्टी नेताओं-अफसरों ने पाला पोसा था, यह बात भी सामने आ चुकी है। इसलिए, गुजरात की विनाश लीला के लिए सिर्फ बिल्डरों को बलि का बकरा बना देने से अपराधी समूची व्यवस्था के खून सने हाथों को धोया नहीं जा सकता। बिल्डर भी उसी व्यवस्था की पैदावार हैं, जिस व्यवस्था की बुनियाद ही लूटपाट, छीना-झपटी और सेंधमारी पर टिकी हुई है।

गुजरात के भूकम्प ने मानवीय संवेदनशीलता का नकाब ओढ़े धर्मरक्षक संघ परिवार और उसके सभी रामभक्तों-शिवभक्तों की सारी महिमा को भी ध्वस्त कर दिया है। इस बारे में कई अखबारों में खबरें आ चुकी हैं कि विपदा के समय भी उनकी सबसे बड़ी चिन्ता अपने चेहरों को चमकाने की थी। राहत वितरण का उनका अन्दाज भी म्लेच्छों से धर्मयुद्ध लड़ने जैसा था। स्पेन और जापान आदि देशों से आयी राहत सामग्रियों का तो उन्होंने अपहरण ही कर लिया और दूसरे कई जगहों से आयी राहत सामग्रियों का वितरण भी अपने झण्डे बैनर के नीचे ही करने के लिए वे अधिकारियों पर जोर-जबर्दस्ती करते रहे।

भूकम्प के बाद गुजरात में मची विनाशलीला के सूत्रधारों को अब भूमण्डलीकरण के विनाश रथ को आगे दौड़ाने का एक नया बहाना भी मिल गया है। नये-नये टैक्सों को थोपना अब आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने कुछ नये टैक्स तुरन्त लगाकर यह चेता भी दिया है कि भूकम्प से तबाह गुजरात को फिर से बसाने के लिए जनता को और अधिक तबाह होने के लिए तैयार रहना होगा।

ऐसे में, देश की मेहनतकश जनता को विनाशलीला के असली सूत्रधारों को पहचानना होगा। हत्यारे हाथों की पहचान करनी होगी। तभी आने वाले समय में प्रकृति के कोप का मुकाबला भी किया जा सकता है और अनगिनत जिन्दगियों को तबाह-बर्बाद होने से बचाया जा सकता है।

ए.एस.पी. का मजदूर आन्दोलन

प्रबन्धतंत्र ने लिखित समझौते को लात मारी

बिचौलिया श्रम विभाग चुप और प्रशासन ने मुंह मोड़ा

(पेज 1 से आगे)

मौका मिलते ही डंसने में बाज नहीं आते। ए.एस.पी. कारखाना मालिकान ने भी यही किया। समझौते के बाद जब मजदूरों ने आन्दोलन रोक दिया तो उसने पलटकर हमला करना शुरू कर दिया।

समझौता यह हुआ था कि 27 दिसम्बर तक सभी 143 स्थायी श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया जायेगा, आन्दोलन के दौरान हुई नयी भर्ती की जगह दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को जरूरत के मुताबिक काम पर रखा जायेगा और पांच जनवरी तक नया वेतन समझौता कर लिया जायेगा।

लेकिन प्रबन्धक लगभग सभी वायदों से मुकर गये। सिर्फ 81 स्थायी मजदूरों को काम पर रखा गया। बाकी को लटका दिया। और नयी-नयी चालबाजियां शुरू हो गयीं। मजदूरों से कहा गया कि उत्पादन बढ़ाओ तो बाकी मजदूर भी । फरवरी तक वापस ले लिये जायेंगे। बहाल हो चुके मजदूरों ने बाहर रह गये अपने साथियों की खातिर उत्पादन बढ़ा भी दिया, लेकिन बचे मजदूरों को फिर भी काम पर वापस नहीं लिया गया। उल्टे अब वर्दी, जूता, कैण्टीन, डी.ए. आदि खत्म करने की जुगत में लग गये। इसके अलावा आन्दोलन की शुरुआत में ही कारखाने से छह माह के लिए निष्कासित किये गये मजदूरों का मामला भी अभी लटका हुआ है और उनकी कोई भी सुनवाई के लिए मालिकान तैयार नहीं हैं।

मालिकों के इस पैंतरापलट और धोखाधड़ी से आजिज आकर मजदूरों ने फिर पुराने स्तर पर उत्पादन करना शुरू कर दिया है और अब मालिकान की झांसापट्टी में न फंसने का मन बना लिया है। हालांकि, पिछले सात माह से वेतन न मिलने के कारण संघर्षरत मजदूर बदहाल हो चुके हैं और दैनिक वेतनभोगी मजदूर तो भुखमरी के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन उनका हौसला अभी टूटा नहीं है। तमाम चालबाजियों के बावजूद प्रबन्धतंत्र काम पर वापस लिये गये और बाहर रह गये मजदूरों और रोजाना मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों की एकता तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। वे एकजुट होकर संघर्ष जारी रखे हुए हैं। उन्होंने प्रबन्धतंत्र की धोखाधड़ी के खिलाफ मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा है। मण्डलायुक्त से लेकर दूसरे प्रशासनिक अफसरों तक का घेराव भी कर रहे हैं। उधर निष्कासित 25 मजदूर भी छह महीने की अवधि पूरी होते देख श्रम न्यायालय में अपील कर चुके हैं। लेकिन मक्कार प्रबन्ध तंत्र और प्रशासन की मिलीभगत से संघर्षरत मजदूरों को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है—मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन, वह भी इसलिए कि मजदूरों ने संघर्ष का रास्ता अभी छोड़ा नहीं है।

लेकिन दमन के तमाम हथकण्डों के बावजूद अभी तक ए.एस.पी. के मालिकान मजदूरों को झुका नहीं सके हैं। अब तक इस आन्दोलन की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। खासकर यह देखते हुए कि गजरौला औद्योगिक क्षेत्र के मालिकों के संगठित आतंक से किसी भी दूसरे कारखाने में संघर्ष की बात तो दूर अभी तक कोई यूनियन तक नहीं बन सकी है। यहां ठेका प्रथा का बोलबाला है और कैजुअल मजदूरों से काम कराना यहां का रिवाज बना हुआ है। ऐसे में ए.एस.पी. के मजदूरों ने मिसाल कायम करते हुए अपना लड़ाकू संगठन बनाया और स्थायी एंव दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के बीच मजबूत एकता कायम की।

ए.एस.पी. के संघर्ष की शुरुआत मजदूरों की यूनियन (ए.एस.पी. इम्प्लाइज यूनियन) ने 5 अप्रैल 2000 को प्रबन्धको को एक मांगपत्र सौंपकर की थी। इसमें जून 2000 से नया वेतन समझौता लागू करने की मांग की गयी थी। लेकिन, इस पर कान देने के बजाय प्रबन्धकों ने शुरू से ही दमन का रवैया अपनाना शुरू कर दिया। कारखाना परिसर के भीतर पचास हथियारबन्द गुण्डों से मजदूरों को आतंकित करने की कोशिश हुई। फिर 25 मजदूरों को निकाल बाहर किया गया और तीन को सस्पेंड किया गया। जब इससे भी मजदूरों की आवाज नहीं दबी तो 16 अगस्त 2000 को गुण्डों और पुलिस के दम पर सभी मजदूरों को कारखाना परिसर से बाहर धकेल दिया गया और उन्हें दुबारा भीतर घुसने से रोक दिया गया। मजबूर होकर मजदूरों ने खुले संघर्ष की शुरुआत की। धरना, प्रदर्शन, अनशन जैसी संघर्ष की कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ जो पिछले समझौते तक चला। इस संघर्ष में क्षेत्र के दूसरे कारखानों के मजदूरों ने भी अपने-अपने जालिम मालिकान की नाराजगी झेलकर भी आन्दोलन को सक्रिय समर्थन-सहयोग देकर अपनी बिरादराना एकजुटता का इजहार किया। हालांकि अपने कारखानों के भीतर वे बहुत अधिक खुलकर सामने नहीं आये लेकिन बाहर ए.एस.पी. के मजदूर भाइयों के साथ संघर्ष में—धरना, प्रदर्शन, जुलूस सभा में शामिल हुए।

इस समय आन्दोलन भीषण कठिनाई का सामना कर रहा है। प्रबन्धतंत्र मजदूरों को आर्थिक रूप से तोड़ देने पर आमादा है, जिससे वह अपनी मनमानी दुगुने जोर से कर सके। लेकिन मजदूरों का मनोबल अभी टूटा नहीं है। उनकी एकता अभी बिखरी नहीं है। लड़ाकूपन कम नहीं हुआ है। ऐसे में अगर इलाकाई मजदूरों का साथ और अधिक मजबूती से मिला और नेतृत्व ने सूझबूझ दिखायी तो ए.एस.पी. के बहादुर मजदूर अपना जायज हक लेकर ही रहेंगे।

मजदूर अकेले-अकेले लड़कर जीत हासिल नहीं कर सकते

(पेज 12 से आगे)

की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ लोगों को भ्रम था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शायद उनके पक्ष में हस्तक्षेप करेंगे। वे यह भूल गये कि इन्हीं वाजपेयी महोदय ने अपने चुनावक्षेत्र लखनऊ में अपट्टान के मजदूरों को प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक कैसे-कैसे वायदे किये थे और बदले में मजदूरों को मिली बेरोजगारी, भुखमरी और पुलिस की लाठियां।

फैक्ट्री की आधी श्रमशक्ति—अस्थायी मजदूरों को किनारे रखकर यूनियन ने पहले ही अपनी ताकत आधी कर ली। अगर उसने शुरू से अस्थायी मजदूरों को साथ लिया होता, उनके अधिकारों के लिए भी आवाज उठायी होती तो आज दोनों मिलकर मैनेजमेण्ट को घुटना टेकने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन मैनेजमेण्ट यहां भी स्थायी और अस्थायी मजदूरों को बांटने में कामयाब रहा। यह कहानी आज हर जगह दोहरायी जा रही है, चाहे वह रुद्रपुर की होण्डा पावर प्रोडक्ट्स हो या मारुति।

आंदोलन के दौरान मारुति के मजदूरों ने अपनी जुझारू एकजुटता के बावजूद संघर्ष के नये-नये तरीके अपनाने, अपने संघर्ष को विस्तार देने, अपनी बातों को व्यापक आबादी के बीच ले जाने की कोशिश नहीं की। राजधानी में सत्ता प्रतिष्ठान की नाक के नीचे एक महीने तक डेरा डालने के दौरान उन्होंने सत्ता की नाक में दम करने की कोशिश नहीं की। दरअसल, उन्होंने सत्ता के गलियारों में घूमने वाले पूंजीपतियों के दलाल नेताओं से तो उम्मीदें पालीं पर जनता के साथ और समर्थन पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। सबसे बढ़कर यह कि मारुति के मजदूरों ने अपने आन्दोलन को अपने ही सेक्टर या दूसरे सेक्टरों की अन्य यूनियनों से जोड़ने की कोशिश नहीं की। आज यह बात तय है कि कोई भी बड़ी से बड़ी यूनियन अकेले-अकेले अपने ही कारखाने या सेक्टर में लड़कर मुकम्मल जीत नहीं हासिल कर सकती। उन्हें अपने तमाम मजदूर भाइयों, दूसरे मेहनतकश तबकों और छात्रों-नौजवानों के संघर्षों के साथ अपने संघर्ष को जोड़ना होगा। भूमण्डलीकरण की लुटेरी नीतियों के खिलाफ चलने वाली लड़ाई को जोड़ना होगा। उन्हें यह महसूस करना होगा कि वे एक व्यापक मजदूर वर्ग के हिस्से हैं जो इस लुटेरी व्यवस्था में रोज अन्याय और जोरो-जुल्म का शिकार हो रहा है।

उन्हें यह समझना होगा कि उनकी लड़ाई सिर्फ इनसेंटिव या किसी और रूप में कुछ सौ रुपये बढ़वा लेने तक सीमित नहीं है। लुटेरी पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर की मुक्ति की लड़ाई तभी पूरी होगी जब उत्पादन, राजकाज और समाज के पूरे ढांचे पर उसका नियंत्रण होगा। वरना वह बाकी मजदूरों से चंद पैसे ज्यादा पाकर भी पूंजी का गुलाम बना रहेगा। और पूंजीवाद के बढ़ते संकट के दौर में मारुति जैसी बड़ी कम्पनियों के मजदूरों के भी अलग-थलग सुरक्षित टापू पर रहने के दिन बीत चले हैं। कोरिया की दाइवू कम्पनी से हजारों मजदूरों की छंटनी महज एक उदाहरण है। खुद मारुति उद्योग का मैनेजमेण्ट 1400 मजदूरों को कम करने और ठेके के मजदूरों की तादाद बढ़ाने की तैयारी में है। मारुति के सरकारी शेयरों को सुजुकी या जनरल मोटर्स के लिए ज्यादा लुभावना बनाने के वास्ते ऐसा किया जा रहा है। ●

दाइवू मोटर कं. के मजदूरों ने संघर्ष तेज किया

दक्षिण कोरिया की विशाल कार कम्पनी दाइवू के हजारों मजदूर लम्बे समय से आन्दोलन की राह पर हैं। कम्पनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और विदेशी खरीदारों के लिए इसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए हजारों मजदूरों की छंटनी करने पर आमादा है।

पिछली 12 फरवरी को दाइवू के तीनों बड़े कारखानों में एक साथ करीब 12 हजार मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। उनके समर्थन में दूसरे मजदूरों और छात्रों ने भी प्रदर्शन किये हैं।

दाइवू के मैनेजमेण्ट ने दिसम्बर 2000 में घोषणा की थी कि वह 16 फरवरी तक 5500 मजदूरों की छंटनी कर देगा ताकि कम्पनी जनरल मोटर्स कारपोरेशन को बेची जा सके। ●

बागडिगी : एक और सामूहिक हत्याकांड

(पेज 1 से आगे)

अगर उत्पादन रोककर सुरक्षात्मक कार्य किया जाता है तो ऊपर के अधिकारी अक्षमता का आरोप लगाते हैं जिसका असर हमारे सर्विस रिकार्ड और पदोन्नति पर पड़ता है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

1955 में गजलीटांड खदान में पानी भरने से 75 मजदूरों की मौत के बाद बनी मुखर्जी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि पानी से भरी जयरामपुर खदान और बागडिगी के बीच कम से कम 120 फीट मोटी कोयले की दीवार छोड़ी जानी चाहिए। लेकिन उत्पादन बढ़ाते जाने के लिए इस दीवाल को काटा जाता रहा। यहां तक कि वह महज 10-20 फीट चौड़ी रह गई थी और पानी रिसना शुरू हो गया था। यह इतनी कमजोर हो गई थी कि जयरामपुर खदान में 1962 से जमा हुआ विषैला पानी 2 फरवरी को इसे तोड़ता हुआ बागडिगी में भर गया। और घटित हुआ एक और चासनाला, एक और गजलीटाण्ड, एक और हत्याकाण्ड।

हत्यारों के शिकार बच न जायें, इसका भी पूरा इंतजाम था। "जिम्मेदार अधिकारियों" के अभाव में निर्णय लेने में देरी के कारण पानी भरने के दो दिन बाद गोताखोरों को बुलाया गया। उन्हें भी अपना काम बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि उनको दिये गये खदान के नक्शे किसी काम के नहीं रह गये थे। उत्पादन बढ़ाने के लालच में नक्शों और सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर मैनेजमेण्ट ने बेमुरव्वती से कोयला कटवाया था।

37 जिन्दा इंसानों की धड़कने किस कदर घुट-घुटकर बंद हुई होंगी इसकी याद भी रोंगटे खड़ी कर देती है। इस भीषण मानवीय त्रासदी के बाद मामले की जांच-पड़ताल के नाम पर हमेशा की तरह जो रस्मी सरकारी कवायद हो रही है वह घिनौनी है, अश्लील है। वही निष्पक्ष जांच की डींगें, निचले कर्मचारियों का निलम्बन, मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने, घड़ियाली आंसू बहाने, शोक संवेदना व्यक्त करने का ठंडा सरकारी प्रहसन। अपनी-अपनी चमड़ी बचाने की अफसरों की हृदयहीन कोशिशें, फरेबी स्पष्टीकरण।

तकनीकी तौर पर अन्ततः खान सुरक्षा महानिदेशालय के किस टेक्नोक्रेट या बीसीसीएल या कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र की किन खामियों से इस बार यह त्रासदी रची गयी, यह महत्वहीन है। ज्यादा जरूरी यह है कि हम मुनाफे की हवस पर टिकी इस जालिम पूंजीवादी व्यवस्था के असली खूंखार चेहरे की शिनाख्त करें, जिसकी हत्यारी तरकीबों का शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने इस तरह पर्दाफाश किया है :

कहीं नहीं है कहीं भी नहीं
लहू का सुराग़
न दस्त-ओ-नाख़ून-ए-क़ातिल
न आस्तीं पे निशां
न सुर्ख़ी-ए-लब-ए-ख़ंजर
न रंग-ए-नोक-ए-सनां
न ख़ाक पे कोई धब्बा
न बाम पे कोई दाग़
कहीं नहीं है कहीं भी नहीं
लहू का सुराग़ ।

● सत्यम वर्मा

हैसवेल शहर के सौ मजदूर

जर्मनी के सर्वहारा कवि **जार्ज वेयेर्थ** की यह कविता 19वीं शताब्दी में लिखी गई थी जब खदानों के निजी मालिक जानवरों की तरह मजदूरों को खदानों में उतारते थे और उनके मरने पर चंद सिक्के पकड़ा देते थे। अभी तक हमारी कोयला खानों का प्रबन्ध उसी हालत में है जैसे यूरोप में उस जमाने में था। भूमंडलीकरण ने इन खदानों के प्रबन्ध को बदतर बनाकर शुरुआती पूंजीवाद के दौर में पहुंचा दिया है क्योंकि उत्पादन और मुनाफा बढ़ाने की कोशिश में अफसरान ने सबसे सस्ती चीज—मजदूर की जान—को दांव पर लगा दिया है।

हैसवेल के सौ मजदूर
मारे गये वे एक ही दिन
मारे गये वे एक ही घंटे
मारे गये वे एक ही ढंग से

और जब उन्हें दफनाया जा रहा था चुपचाप
वहां पहुंचीं एक सौ औरतें
और हैसवेल की सौ औरतें रोयीं
हैसवेल शहर के मृतकों के लिए ।

वे आयीं लिये हुए अपने छोटे बच्चे
और अपने बच्चों के बच्चे
'हैसवेल शहर के ओ अमीर मालिक,
हमारा कर्ज है तुम पर, चुकाओ उसे !'

हैसवेल की खदानों के मालिक ने
सोचने में नहीं किया ज्यादा विलम्ब
फटाफट गिनकर थमायी उन्हें
उस हफ्ते की मजदूरी की बाकी रकम !

और गिनते ही ये चंद सिक्के
बंद कर दी तिजोरी जोर से
भड़ाम से बंद हुआ भारी सा फाटक
और रो पड़ीं औरतें फिर जोर से ।

काशीपुर (उड़ीसा) में अल्युमिनियम कारखाने के लिए उजाड़ी जा रही आदिवासी जनता पर पुलिस फायरिंग

उड़ीसा के रायगढ़ जिले के काशीपुर ब्लाक में एक विराट अल्युमिनियम कारखाना लगाये जाने के खिलाफ लम्बे समय से आन्दोलन चला रहे आदिवासी किसानों पर पिछली 16 दिसम्बर को माइकुंच गांव में अंधाधुंध गोलियां चलाकर पुलिस ने तीन लोगों को मार डाला और 30 से ज्यादा को जख्मी कर दिया। इलाके में पुलिस और कम्पनी के गुण्डों के आतंक के बावजूद लोगों का संघर्ष जारी है।

इस घटना ने देशी-विदेशी लुटेरी कम्पनियों और उनकी सेवा में बेशर्मी से जुटी सभी राजनीतिक पार्टियों का घिनौना चेहरा तो उजागर किया ही है, जनता के बीच भ्रम फैला रहे स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) की असली भूमिका को भी नंगा किया है।

पूंजीवादी समाज में लोग नहीं बल्कि मुनाफा केन्द्र में होता है। विकास का असल मकसद मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियां भरना होता है, चाहे इसके लिए भारी आबादी का विनाश ही क्यों न हो जाये। इसीलिए इस समाज में विकास की तमाम परियोजनाएं लोगों को उजाड़कर, उन्हें अपनी जगह-जमीन से बेदखल करके, आजीविका के साधनों से वंचित करके ही आगे बढ़ती हैं। समाज के कमजोर और दबे-कुचले हिस्से इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। यही वजह है कि प्रायः जनता को अपने अस्तित्व के लिए विकास की योजनाओं के ही खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। काशीपुर में यही हो रहा है।

इस इलाके में 4500 करोड़ की लागत से विशाल अल्युमिनियम कारखाना और बाक्साइट की खदानें शुरू करने की राज्य सरकार, पुलिस और उद्योगपतियों की मिली-जुली कोशिश के खिलाफ 1993 से ही स्थानीय आबादी लड़ रही है। प्राकृतिक सम्पदा सुरक्षा परिषद के तहत आदिवासी जनता इस बात पर दृढ़ है कि वह उन्हें उजाड़ने और उनकी जमीन और जंगल को तबाह व प्रदूषित करने वाले कारखाने और खदानों को यहां लगने नहीं देंगे।

बाक्साइट के प्रचुर भंडारों वाले इस इलाके पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नजर बहुत पहले से गड़ी रही है। उत्कल अल्युमिनियम इंटरनेशनल लिमिटेड (यू ए आई एल) नाम की जो कम्पनी पूरी तरह निर्यात-निर्देशित कारखाना लगा रही है उसमें 45 प्रतिशत हिस्सा नार्वे की हाइड्रो अल्युमिनियम का और 35 प्रतिशत हिस्सा कनाडा की एलकान कम्पनी का है। शेष 20 प्रतिशत इंडियन अल्युमिनियम कं. के पास है जिसे अब आदित्य बिड़ला ग्रुप (हिंडाल्को) ने खरीद लिया है। यू ए आई एल ने अब तक 2115 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली है जिस पर उसने एक हवाई पट्टी भी बना डाली है। उसे कुल 1750 हेक्टेयर जमीन लेनी है जो काशीपुर ब्लाक के 24 गांवों में फैली हुई है। पर्यावरण मंत्रालय ने फटाफट 1995 में उसे स्वीकृति दे दी थी और तमाम विरोध के बावजूद उड़ीसा खनन निगम ने भी पिछले वर्ष नवम्बर में उसे बाक्साइट खनन के लिए लीज दे दी। तभी से कम्पनी और उसकी चाकर सरकार किसी भी कीमत पर पूरी जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

स्थानीय आबादी के पास इस जमीन और 330 प्राकृतिक जलधाराओं वाले जंगल के सिवा आजीविका का और कोई जरिया नहीं है। परियोजना के लिए जमीन छीन लेने और जंगल नष्ट कर देने के बाद उनके सामने दो ही रास्ते बचेंगे—भुखमरी झेलना या अपने घरों से उजड़कर महानगरों की झुग्गी बस्तियों के नर्क में शामिल हो जाना। हर परिवार को रोजगार के वायदों को इन कम्पनियों ने कितनी बेहयाई से लात मारी है उसके उदाहरण चारों ओर फैले पड़े हैं। इसी वायदे को पूरा करने की मांग कर रहे किसानों पर बबराला में टाटा के इशारे पर पुलिस ने गोलियां बरसाकर आठ लोगों को भून डाला था।

काशीपुर में आंदोलन 1993 से लगातार तेज होता गया है। पुलिस के साथ ही कम्पनी के भाड़े के गुण्डों ने किसानों को डराने-धमकाने में कोई कसर नहीं उठा रखी लेकिन जनता का प्रतिरोध इतना तगड़ा रहा है कि कई गांवों में पुलिस या गुंडों की घुसने की भी हिम्मत नहीं होती है। दूर-दराज तक के इलाकों में अपनी बात पहुंचाने के लिए परिषद लगातार पदयात्राएं और सभायें तो करती ही रही हैं, हाट-बाजार से लेकर शादी-ब्याह जैसे मौकों तक पर लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर यह उनकी जिन्दगी और मौत का सवाल है।

दल्लों की भूमिका में हैं तमाम चुनावी पार्टियां

पिछले 15-16 दिसम्बर को जो हुआ वह इस आन्दोलन को कुचल डालने के लिए सरकार, कम्पनियों और राजनीतिक पार्टियों की मिली-जुली साजिश का नतीजा था। प्राकृतिक सम्पदा सुरक्षा परिषद ने 20 दिसम्बर को 'रास्ता रोको' का आह्वान किया था। तमाम गांव वाले इसकी तैयारी में जुटे थे। दूसरी ओर पुलिस, कम्पनी और सभी चुनावी पार्टियों में बैठे उनके चाकर स्थानीय जनता की ताकत और एकजुटता के इस प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए कुछ भी करने पर आमादा थे।

कारखाना हर कीमत पर लगवाने और आदिवासियों के संघर्ष को कुचलने के लिए सभी रंग की राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक सर्वदलीय समिति तक बना डाली। इसमें बीजू जनता दल, भाजपा और कांग्रेस प्रमुख हैं। रास्ता रोको के ठीक पांच दिन पहले 15 दिसम्बर को परियोजना के समर्थन में माइकुंच में सर्वदलीय सभा रखी गई। स्थानीय जनता ने जब इसका विरोध किया तो बीजद के गुण्डों और कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। ठीक अगले दिन हथियारबन्द पुलिस ने गांव पर छापा मारा। पुलिस के आने की चेतावनी पाकर गांव के पुरुष पास की पहाड़ियों में चले गये थे सिर्फ महिलाएं और दो-तीन नौजवान गांव में रह गये थे। रास्ते में पुलिस ने एक ग्रामीण को डरा-धमका कर कुछ नौजवानों के नाम पता कर लिये थे। गांव के बाहर सात और दस वर्ष के दो बच्चे पुलिस को मिल गये जिनसे पुलिस वालों ने उन लोगों का अता-पता पूछा। इसके बारे में कुछ भी जानने से इंकार करके डर से जब बच्चे भाग रहे थे तो पुलिस वालों ने गोली चला दी जिससे एक बच्चा घायल हो गया और दूसरे का आज तक पता नहीं चला है। गांव में पहुंच कर पुलिस वालों ने औरतों को मारा-पीटा लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद पुलिस वालों ने पहाड़ियों की दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो भी गांव वाला नजर आया उस पर गोलियां चलायी गईं। घायलों के नाक, चेहरे, गर्दन और पेट में लगी हुई गोलियां खुद उस दिन की कहानी बताती हैं। तीन लोग मारे गये और दर्जनों घायल हुए। कई नौजवान आज तक लापता हैं।

इस बर्बर दमन के बावजूद गांव वाले दबे नहीं और रास्ता रोको के दिन रूपकाना में आठ हजार लोग इकट्ठा हुए। माइकुंच जहां पुलिसिया तांडव हुआ था वहां से भी दो दिन पैदल चलकर 500 लोग प्रदर्शन में पहुंचे थे।

एनजीओ की असली भूमिका

उड़ीसा भर में मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में यह बताया कि कुछ बाहरी लोग मासूम आदिवासियों को भड़का रहे हैं। इन आदिवासियों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस के वाहन जलाये और मजबूर होकर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यहां बाहरी लोगों से मतलब था 'अग्रगामी' नाम का एनजीओ जो इस पूरे मामले में कहीं था ही नहीं। लेकिन एनजीओ के बहाने मीडिया ने एक के बाद एक झूठ परोसना और जनता के पूरे आन्दोलन को बहका हुआ बताया और एनजीओ की भूमिका पर सवाल खड़ा करके मुद्दे से ध्यान भटकाने में काफी हद तक सफल रहा।

यह एक संयोग ही था कि फायरिंग की घटना के दो दिन पहले विधानसभा में उड़ीसा में एनजीओ की भूमिका को लेकर जोरदार बहस हो रही थी। तूफान के बाद राहत कार्यों में एनजीओ के भ्रष्टाचार को लेकर भी मीडिया में और जनता में काफी सुगबुगाहट थी। कुछ मंत्रियों और नौकरशाहों के एनजीओ के बड़े मठाधीशों के साथ निजी झगड़ों की वजह से भी एनजीओ के खिलाफ वहां माहौल बनाया गया।

जहां तक 'अग्रगामी' का सवाल है इस एनजीओ ने उस इलाके में परियोजना बनने से जीवन, आजीविका तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चंद एक रिपोर्टें छापने और थोड़ा बहुत प्रचार करने के सिवा कुछ नहीं किया था। इतना करना भी उसके लिए जरूरी था क्योंकि वह

(पेज 2 पर जारी)

पंजीयन संख्या - 71980/99 डाक पंजीयन संख्या LW-NP/349/2000

मारुति के मजदूरों का साढ़े तीन माह तक चला जुझारू आन्दोलन समझौते के बाद समाप्त

मजदूर अकेले-अकेले लड़कर जीत हासिल नहीं कर सकते

मारुति के मजदूरों के लम्बे आन्दोलन के समापन के तुरन्त बाद लिखी गई यह रिपोर्ट संपादकीय कार्यालय को देर से मिलने के कारण 'बिगुल' के पिछले अंक में नहीं जा पायी थी। मारुति के आन्दोलन ने बड़े उद्योगों में संगठित मजदूरों की स्थिति के बारे कई भ्रमों को तोड़ा है और कई सवाल सामने लाये हैं जिनपर जागरूक मजदूरों और मजदूर आन्दोलन से जुड़े सभी लोगों को सोचना होगा।

इस आन्दोलन के दौरान बुर्जुआ प्रेस ने अपना असली रंग जमकर दिखाया। राजधानी दिल्ली में संसद, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के ऐन सामने उद्योग भवन में साढ़े चार हजार मजदूर जाड़े-पाले-बरसात में खुले आसमान के नीचे एक महीने तक डेरा डाले रहे लेकिन दिल्ली से निकलने वाले दर्जनों अखबारों और टीवी चैनलों में से चंद एक में ही उनकी आवाज कभी-कभार जगह पा सकी। जबकि इसी बीच मारुति के मैनेजमेण्ट ने लाखों रुपये के विज्ञापन इन सबको बांटे। और तमाम झूठ परोसे जिन्हें मारुति में चलने वाले पत्रकारों ने आंख मूंदकर छापा। (इस घटना ने एक बार फिर मजदूरों के एक ऐसे व्यापक पहुंच वाले अखबार की जरूरत का शिद्दत से अहसास कराया जो अलग-अलग लड़ रहे मजदूरों के संघर्षों को एक लड़ी में पिरोने का आधार बने। जो अलग-अलग आन्दोलनों की जीतों-हारों से सबक लेने और व्यापक मजदूर एकता की दिशा में बढ़ने में मजदूरों के शिक्षक और दोस्त की भूमिका निभाये।

अभी कुछ ही सप्ताह पहले आटोमोबाइल सेक्टर की एक दूसरी बड़ी कम्पनी टेल्को की लखनऊ इकाई में ठीक इसी तरह से धोखाधड़ी और गुंडागर्दी के जरिये मैनेजमेण्ट ने जबरन तालाबंदी कराई थी। लम्बे आन्दोलन के बाद भी वहां सभी बर्खास्त मजदूरों को वापस नहीं लिया गया। (बिगुल के अंक.... में इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी गई है।) उस आन्दोलन की जानकारी मारुति के मजदूरों को नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे मारुति के आन्दोलन से टेल्को और देश के तमाम इलाकों के मजदूर नावाकिफ रहे। (राजधानी के कारण छिटपुट खबरें जरूर अखबारों में आ गईं।)

इसीलिए हम इस विस्तृत रिपोर्ट को 'बिगुल' के पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। - सम्पादक

(बिगुल संवाददाता)

नई दिल्ली, 15 जनवरी। मारुति उद्योग लिमिटेड के साढ़े चार हजार स्थायी मजदूरों का साढ़े तीन माह से भी लम्बे समय तक चला जुझारू आन्दोलन आखिरकार 9 जनवरी को मैनेजमेंट के साथ समझौते के बाद समाप्त हो गया।

इसी के साथ पिछले 13 दिसम्बर से भीषण ठण्ड और बरसात तक की परवाह किये बिना दिल्ली के उद्योग भवन पर डेरा डाले हजारों मजदूर वापस लौट गये हैं।

यह समझौता एक रूप में मजदूरों की हार है। उन्हें मैनेजमेंट की प्रोत्साहन (इनसेंटिव) योजना स्वीकार करनी पड़ी है जिसके विरोध में आन्दोलन की शुरुआत हुई थी और आन्दोलन के दौरान कम्पनी से निकाले गये 80 मजदूरों में से सिर्फ 41 को ही वापस लेने के लिए मैनेजमेंट तैयार हुआ है, वह भी "अच्छे व्यवहार" का निजी मुचलका भरवाने के बाद। सबसे बढ़कर, जिस 'गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग' के खिलाफ पिछले तीन माह से मजदूर सड़कों पर थे उसपर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो पाया। यूनियन का दावा है कि इसे वापस ले लिया गया है जबकि मैनेजमेंट का कहना है कि इसे वापस नहीं लिया गया है और यूनियन ने सभी कर्मचारियों की ओर से इसपर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया है। आन्दोलन खत्म होने के बाद से मैनेजमेण्ट का रवैया और भी हमलावर हो गया है।

हाल के दिनों में एक बड़े संगठित उद्योग के इस सबसे लम्बे चले आन्दोलन और इसकी समाप्ति—दोनों ने ही कई ऐसे जरूरी सवाल उभारे हैं जिनपर सभी जागरूक मजदूरों को संजीदगी से सोचने और भावी संघर्षों के लिए सबक निकालने की जरूरत है।

यह एक विडम्बना है कि इतने लम्बे समय तक चले इस आन्दोलन की परिस्थितियों, उसकी मांगों और मारुति के मजदूरों की वास्तविक स्थिति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए संक्षेप में इसकी चर्चा यहां जरूरी है।

●

पचास प्रतिशत सरकारी और पचास प्रतिशत जापानी भागीदारी वाले मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई। पिछले 18 वर्षों में हजारों मजदूरों ने कमरतोड़ मेहनत करके कम्पनी के लिए अकूत मुनाफा पैदा किया। एक ओर कम्पनी लगातार उत्पादन बढ़ाकर अपना मुनाफा और मजदूरों का शोषण बढ़ाती गई और दूसरी ओर मीडिया के जरिए यह प्रचारित किया गया कि मारुति के कर्मचारी देश के बाकी मजदूरों से अलग मानो स्वर्ग में रहते हैं। हल्के संगीत की धुन पर काम करते और अफसरान के साथ एक ही कैंटीन में लंच करते मजदूरों की छवियां प्रचारित की गईं लेकिन मारुति के मजदूरों के आन्दोलन ने इस झूठ को तार-तार कर दिया।

आन्दोलन की शुरुआत उत्पादकता -आधारित इनसेंटिव को लेकर हुई। 1988 में मैनेजमेंट ने मारुति उद्योग इम्प्लाइज यूनियन के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत मजदूरों के मासिक वेतन के एक हिस्से को उत्पादकता के साथ जोड़ दिया गया था। इसके तहत प्रति मजदूर प्रति वर्ष 41.5 कारों के उत्पादकता स्तर से ऊपर उत्पादन होने पर मजदूरों को श्रम की लागत पर होने वाली बचत का 65% मिलना था। यह योजना भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई और 1995 तक लागू रही।

1995-96 में मारुति मैनेजमेंट ने एकतरफा तौर पर योजना की शर्तें बदल दीं जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों को मिलने वाले इनसेंटिव में काफी कमी आ गई। 1988 में प्रति वर्ष एक लाख कारें बनाने वाले मारुति के मजदूरों ने 1995 में दो लाख कारें बनाईं और 1999-2000 में चार लाख कारें। उत्पादकता में इस तेज बढ़ोत्तरी के कारण ही मैनेजमेंट को बढ़ा हुआ इनसेंटिव देना खटकने लगा। हालांकि उत्पादन और बढ़ाने के लिए वह मजदूरों पर दबाव भी बढ़ाता गया।

यूनियन पिछले 19 माह से यह मांग कर रही थी कि मैनेजमेंट 1988 के समझौते के अनुसार इनसेंटिव लागू करे। यूनियन की अन्य मांगों में पहले के समझौते के मुताबिक पेंशन योजना लागू करना प्रमुख था। वह वार्षिक उत्पादन लक्ष्य भी निश्चित करने की मांग कर रही थी ताकि हर मजदूर पर पड़ने वाले काम के बोझ और तनाव को सीमित किया जा सके।

इनमें से किसी भी मुद्दे पर मैनेजमेंट के अड़ियल रुख में कोई बदलाव नहीं आने पर सितम्बर के पहले हफ्ते में मजदूरों ने गेट मीटिंगें शुरू कीं और 18 सितम्बर से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। जवाब में मैनेजमेंट ने 14 मजदूरों को बर्खास्त और 12 को निलम्बित कर दिया जिनमें यूनियन के पदाधिकारी भी थे। 3 अक्टूबर से यूनियन ने हर शिफ्ट में दो घंटे का टूल डाउन शुरू किया। साथ ही यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये।

इस स्थिति में भी मैनेजमेंट ने वार्ता या यूनियन की मांगों पर कोई जवाब देने के बजाय पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से जबरन भूख हड़ताल तुड़वा दी और फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर यूनियन नेताओं को जेल भिजवा दिया। और घटियाई पर उतरते हुए मैनेजमेंट ने यूनियन कार्यालय के टेलीफोन और बिजली के कनेक्शन काट दिये।

इसी के बाद 12 अक्टूबर को मैनेजमेंट ने मजदूरों पर 'गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग' थोपकर उन्हें कारखाने से बाहर कर दिया और उल्टा उनपर बेवजह हड़ताल करने की तोहमत मढ़ दी। 12 अक्टूबर को जब सुबह की शिफ्ट के मजदूर दिल्ली की सीमा पर पालम-गुड़गांव रोड पर स्थित फैक्ट्री पर पहुंचे तो गेट पर ताला जड़ा था और मैनेजमेंट का यह आदेश कि 'गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग' पर दस्तखत करने के बाद ही कोई मजदूर भीतर जा सकता है। इस शपथपत्र में लिखा था कि "मैं धीमे काम करने, टूल डाउन, हड़ताल या ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लूंगा जिससे उत्पादन या अनुशासन पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो..." मैनेजमेंट की यह मांग बिलकुल गैरकानूनी थी। कोई भी कानून मजदूरों को किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो उनके बुनियादी राजनीतिक अधिकारों पर अंकुश लगाता हो।

इस जबरन तालाबंदी के खिलाफ दो महीने तक फैक्ट्री गेट पर संघर्ष करने के बाद 13 दिसम्बर से हजारों मजदूरों ने मारुति के 50% की मालिक सरकार से न्याय मांगने केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय के दफ्तर उद्योग भवन पर डेरा डाल दिया जो आन्दोलन खत्म होने तक जारी रहा। इस बीच मैनेजमेंट लगातार अड़ियल रवैया अपनाये रहा। कई और कर्मचारियों को निकाल दिया गया। मजदूरों को डराने-धमकाने, गुण्डों से पिटवाने और फर्जी मुकदमों में फंसाने के पुराने हथकण्डे भी अपनाये गये लेकिन कुछ सौ मजदूरों के अलावा मैनेजमेंट किसी को अंडरटेकिंग भरवाकर फैक्ट्री के भीतर नहीं ले जा पाया।

अस्थायी मजदूरों की भारी संख्या

मारुति में सीधे 'प्रोडक्शन लाइन' पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर स्थायी हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अस्थायी मजदूर हैं जिनके बिना उत्पादन सम्भव ही नहीं हो सकता है। श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन कर इन अस्थायी मजदूरों को मामूली मजदूरी पर बुरी तरह निचोड़ा जाता है। फैक्ट्री में करीब 3000 ठेका मजदूर हैं जिनमें से आधे पेंट शाप और मशीन शाप में काम करते हैं। करीब 750 मजदूर मैटेरियल हैंडलिंग में लगे हैं जो प्रोडक्शन लाइन से सीधे जुड़ा है। शेष ठेका मजदूर सफाई, कैंटीन और सिक्योरिटी में लगे हैं। इन्हें 50 से 60 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलती है और दूसरे मजदूरों को मिलने वाले कोई इनसेंटिव इन्हें नहीं मिलते।

इनके अलावा 1100 से ज्यादा युवा अप्रेंटिस यहां काम करते हैं जो स्थायी नौकरी की आशा में एक वर्ष तक सिर्फ 600 रुपए प्रतिमाह पर खटते हैं। इनमें से ज्यादातर को एक वर्ष के बाद हटा दिया जाता है। कुछ अप्रेंटिसों को ट्रेनी के तौर पर रखा जाता है और दो वर्ष तक और खटाने के बाद स्थायी किया जाता है। इस तरह मारुति उद्योग के मजदूरों की वास्तविक संख्या 9000 से भी ज्यादा है और इनमें से आधे से ज्यादा अस्थायी हैं जिससे कम्पनी हर वर्ष करोड़ों रुपए बचाती है।

इन्हीं ठेका मजदूरों और अप्रेंटिसों के सहारे मैनेजमेंट 12 अक्टूबर के बाद थोड़ा-बहुत उत्पादन चलाता रहा। इनसे 12-12 घंटे काम लिया जाता रहा और दूसरी तरफ स्थायी मजदूर उन्हें हड़ताल तोड़ने वालों के रूप में देखते रहे।

यदि मारुति उद्योग यूनियन ने शुरू से ही ठेका मजदूरों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया होता तो इस आन्दोलन में समस्त मजदूरों के संयुक्त संघर्ष की ताकत कई गुना बढ़ गई होती और उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया होता।

मीडिया में झूठा प्रचार और वास्तविक मजदूरी

मैनेजमेंट बुर्जुआ मीडिया में ऐसे झूठे किस्से छपवाता रहा है कि मजदूरों पर कम्पनी 23,000 रुपए हर महीने खर्च करती है और वे 42,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। जबकि असलियत यह है कि सबसे अनुभवी मजदूर अधिकतम उत्पादकता के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा 14,000-16,000 रुपए पा सकता है। आम तौर पर इनसेंटिव को जोड़कर भी 10,000-11,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिलते।

वर्ष 1999-2000 में कम्पनी की कुल बिक्री से हुई आय में दिये गये वेतन का हिस्सा सिर्फ 2 प्रतिशत था। इसमें मैनेजमेंट के वेतन-भत्ते शामिल हैं। अगर सिर्फ मजदूरों की मजदूरी जोड़ी जाए तो यह कुल बिक्री का महज 0.85 प्रतिशत बैठेगा। बाजार में कम से कम सवा दो लाख की बिकने वाली हर मारुति कार में लगने वाले श्रम की कीमत इस हिसाब से सिर्फ 1950 रुपए पड़ती है!

मजदूरों के श्रम की लूट की बदौलत मारुति का मुनाफा साल-दर-साल लगातार बढ़ता ही गया है। उत्पादन और उत्पादकता में भारी बढ़ोत्तरी के लिए आटोमेशन तथा नई तकनोलाजी एक हद तक ही जिम्मेदार रहे हैं। असली वजह मजदूरों पर काम का बढ़ता बोझ।

इतनी ऊंची उत्पादकता लेने के लिए मजदूरों को बुरी तरह निचोड़ा जाता है। वे साढ़े आठ घंटे की शिफ्टों में काम करते हैं जिस दौरान उनपर कड़ी नजर रखी जाती है। आधे घंटे के लंच के अलावा बीच में 7-7 मिनट के दो ब्रेक मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें गर्दन सीधी करने की भी फुरसत नहीं मिलती। पानी पीने और पेशाब करने के लिए भी अलग से छूट नहीं मिलती। एक मजदूर ने इस संवाददाता को बताया कि एक साल में कुल मिलाकर 16 छुट्टियों (साप्ताहिक अवकाश सहित) से ज्यादा लेने पर इनसेंटिव से कटौती शुरू हो जाती है। इसलिए मजदूर मशीन की तरह काम में जुते रहते हैं। इस निरन्तर दबाव के चलते मारुति के मजदूर तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

●

निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों का दौर शुरू होने के बाद से खासकर संगठित क्षेत्र में मजदूर आन्दोलन ने एक के बाद एक पराजयें देखी हैं। रेलवे और डाककर्मियों से लेकर बैंक-बीमा जैसे सार्वजनिक उद्यमों में चुनावी पार्टियों से जुड़ी यूनियनों के नेतृत्व की गद्दारी ने कई संघर्षों को हार का मुंह दिखाया है।

ऐसे में मारुति के आन्दोलन से बहुत से लोगों को उम्मीदें थीं कि यह सिर्फ आटोमोबाइल सेक्टर ही नहीं बल्कि तमाम उद्योगों के मजदूरों को नया हौसला देगा। यहां की यूनियन सीधे किसी चुनावी पार्टी से नहीं जुड़ी थी और यूनियन नेताओं तथा आम मजदूरों के बीच उस तरह की अफसरशाही का रिश्ता नहीं था जैसा कि आजकल ज्यादातर पुरानी यूनियनों में है। और मजदूरों का बहुमत संघर्ष को निर्णायक मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार था।

इसके बावजूद इस आन्दोलन का इस तरह से समाप्त होना कुछ जरूरी मुद्दों पर सोचने के लिए विवश करता है।

कुछ जरूरी नतीजे, कुछ जरूरी सबक

आन्दोलन के दौरान यह बात सामने आयी कि यूनियन नेतृत्व संसदीय नेताओं से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पालता रहा। वह कभी लाल झण्डे के सौदागर नकली वामपंथियों की ओर तो कभी डाला-चुर्क में मजदूरों का कत्लेआम कराने वाले मुलायम सिंह यादव की पार्टी की ओर देखता रहा। संसद में मारुति के मजदूरों के सवाल पर गर्मागर्म बहसें करने वाले नेताओं को वह सचमुच मजदूरों का हितैषी समझने की भूल करता रहा। वह इस सच्चाई को नहीं देख पाया कि ये सारी पार्टियां निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों पर एकमत हैं। सबकी व्यक्त-अव्यक्त सहमति से मारुति के पूर्ण निजीकरण

(पेज 10 पर जारी)

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी डा. दूधनाथ द्वारा 69, बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित एवं उन्हीं के द्वारा वाणी ग्राफिक्स, अलीगंज, लखनऊ से मुद्रित। कम्पोजिंग: कम्प्यूटर प्रभाग, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
संपादक: डा. दूधनाथ। सम्पादकीय पता: द्वारा ओ.पी. सिन्हा, 69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006. सम्पादकीय उपकार्यालय: जनगण होम्यो सेवासदन, मर्यादपुर, मऊ।